सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-29 अंक-19 7 से 21 अक्तूबर, 2014 मुख्य संपादक - कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती मूल्य : 2 रुपये

सबके लिए बैंक खाता—एक बाजीगरी

बहुत धूम-धाम के साथ हॉल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री जन-धन योजना के लिए बुर्जुआ मीडिया ने नरेन्द्र मोदी की खूब वाह-वाही की है। हमारे देश में प्रत्येक परिवार को औपचारिक बैंकिंग के दायरे में लाने के लिए यह स्कीम डिजाइन की गई है। अत: प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत कोई व्यक्ति किसी पहचान दस्तावेज के बिना भी तुरन्त बैंक खाता खोल सकता है। खाताधारी को रु पे डेबिट कार्ड भी मिलेगा जिसके साथ 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा जुड़ा हुआ है। जो जनवरी 2015 से पहले अपना खाता खोलेंगे उन्हें 30000 रु. का अतिरिक्त जीवन बीमा मिलेगा। 5000 रु. तक के कर्ज या ओवर ड्राफ्ट की सुविधा भी मिलेगी बशर्ते छ: महीने बाद क्रेडिट रिकार्ड संतोषजनक रहा हो। कालक्रम में इन खातों के माध्यम से सीधे राशि हस्तांतरण की योजना भी मोदी सरकार की है चाहे वह सब्सिडी के लिए हो, खास तरह की पेंशन के लिए हो और जो भी हितलाभ लोगों को प्राप्त होने हों।

पहले दिन रिकार्ड संख्या में 1.5 करोड़ लोगों ने कथित तौर पर बैंक खाता खोला है। स्वतंत्रता दिवस 2015 तक 7.5 करोड़ परिवारों द्वारा खाता खोले जाने का लक्ष्य है। मोदी सरकार का कहना है कि यह गरीबों की बहुसंख्या को 'वित्तीय समावेश' में लाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन के तौर पर प्रधानमंत्री जन-धन योजना को प्रोत्साहित कर रही है। इस प्रकार हमारे देश में जहाँ 68% आबादी की बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच नहीं है इस छोड़ाव को दूर करना होगा। इस स्कीम के लिए यह दावा करते हुए सम्पूर्ण बुर्जुआ मीडिया ने नरेन्द्र मोदी पर प्रशंसा की झड़ी लगा दी है कि इस स्कीम को लागू करके उन्होंने खुद ही दिखा दिया है कि वे केवल गुफ्तार के ही गाजी नहीं बल्कि किरदार के भी गाजी हैं जिन्होंने लोगों के लिए 'अच्छे दिन' के वायदे को निभाया है। हालांकि 'आधार' के जरिए सीधे कैश ट्रांसफर लागू करने के यूपीए के प्रयास गच्चा खा गए फिर भी भरोसा जताया जा रहा है कि मोदी इसे कार्यकारी करने में सक्षम होंगे और 'निरंकुश अफसरशाही के चंगुल' से लोगों को मुक्त करने के तरीके के रूप में सीधे कैश ट्रांसफर की प्रशंसा की जा रही है। अब देखें, प्रधानमंत्री जन-धन योजना असल में कैसे काम करती है?

योजना

देखिए कितना आसान बना दिया गया है कि एक अर्ध-शिक्षित या अशिक्षित व्यक्ति भी जो अब तक बैंक में प्रवेश करने का साहस तक नहीं कर पाता था अब प्रवेश कर सकता है या सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों द्वारा सड़क किनारे खोले गए ग्राहक सेवा केन्द्र के पास जा सकता है और आधार कार्ड प्रस्तुत करके जीरो बैलेंस बचत बैंक खाता तुरन्त खोल सकता है। लेकिन आधार कार्ड भी कोई अनिवार्य नहीं है, सिर्फ एक फोटो और अंगूठे का निशान लगाना ही काफी है। बैंक खाता धारकों के लिए के वाई सी (अपने ग्राहक को जानिए) के साथ जुड़ी तमाम औपचारिकताओं को धता बता दी गई है।

इसलिए कहा जा रहा है कि वे लोग जो बेईमान पोंजी स्कीमों की शिकारगाह बने हुए थे, अब अपनी कष्टसाध्य बचतों को सुरक्षित रख सकेंगे। ऐसी हवा बनाई जा रही है कि इस प्रधानमंत्री जन-धन योजना का वास्तव में ही परिवर्तनकारी प्रभाव होगा और विशेषकर खातों से जुड़ी बीमा स्कीमों के जरिए प्रदान की जाने वाली सामाजिक सुरक्षा जो दुखद रूप से हमारे देश में नदारद है। सुनने में लगता है जैसे सपना सच हो गया, क्या नहीं हुआ? ठहरिए : शर्तें लागू हैं। हालांकि स्पष्ट रूप से इनका उल्लेख नहीं किया गया है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक 6 महीने बाद भी ऐसे किसी खाते को जारी रखने के लिए लोगों को इसी दौरान स्थानीय विधायक या काऊंसलर से एक पत्र लेना होगा। कुछ भी नहीं बताया गया है कि एक अर्ध-शिक्षित या अशिक्षित व्यक्ति जिसके पास पहचान का कोई प्रमाण नहीं है वह ऐसा एक पत्र कैसे हासिल कर सकता है, क्या-क्या दस्तावेज या औपचारिकताएं जरूरी हैं। चाहे जो भी हो, यह मान लिया जाए कि अधिकतर न सही, अगर बहुत से लोग इस बाधा को सफलतापूर्वक पार कर लेगें, चाहे आसानी से हो या मुश्किल से। असल में, प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत वित्तीय समावेश के लिए मिशन का आधार के जरिए 'सीधे कैश ट्रांसफर' के माध्यम से यूपीए सरकार द्वारा 2010-11 में लागू किए गए ''वित्तीय समावेश के लिए मिशन'' से कुछ खास तफर्का नहीं है। आइए अब प्रधानमंत्री जन-धन योजना के विभिन्न पहलुओं की एक एक कर पड़ताल करें।

बैंकों की पर्याप्त ब्रांचों के अभाव में बिचौलियों के रूप में कार्य करेंगे बिजनैस कॉरस्पोंडेंट

इस तथ्य के मद्देनजर कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाएं बहुत कम और दूर-दूर स्थित हैं, इसके अलावा, क्योंकि भूमण्डलीकरण ने बैंकों में अधिकाधिक शाखाओं के बन्द करने का रुझान ला दिया है। इनमें से सैकड़ों कस्बों-शहरों में भी हैं—इसलिए बैंकिंग लेन-देन को जारी रखने के लिए बैंकों और ग्राहकों के बीच मध्यस्थ के रूप में स्थानीय एजेण्टों को नियुक्त किया गया है जिन्हें बिजनैस कॉरस्पोंडेंट भी कहा जाता है। इस प्रकार, ग्रामीण रोजगार (नरेगा) स्कीम के लिए बिजनैस कॉरस्पोंडेंट मॉडल पर आधारित एक तरह की शाखाहीन बैंकिंग को लागू किया गया था। इस तथ्य के साथ-साथ कि बिजनैस कॉरस्पोंडेंट मॉडल बहुत सी तकनीकी खामियों व समस्याओं से ग्रस्त था, भ्रष्टाचार भी बढ़ गया था।

मौजूदा प्रधानमंत्री जन-धन योजना को लागू करने के लिए उसी बिजनैस कॉरस्पोण्डेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। इस संदर्भ में यह याद करना जरूरी है कि राजीव गांधी तक को भी एक समय यह स्वीकारना पड़ा था कि लोगों के फायदे या कुछ स्कीमों के लिए सरकार द्वारा मंजूर या खर्च किए गए प्रत्येक 1 रुपये में से उन तक सिर्फ 10 पैसे पहुँचते हैं। यूपीए-2 शासन के दौरान सीधे कैश ट्रांसफर को इस रूप में प्रचारित किया गया था कि यह ऐसे रिसाव को दूर करने और बिचौलियों के उन्मूलन में सक्षम होगा जो लोगों को उनके जायज पावने से वंचित करने में अपनी भूमिका के लिए कुख्यात हैं। लेकिन उस समय आलोचकों ने इंगित किया था कि व्यवस्था में जानबूझकर की गई हेराफेरी के जरिए छोड़ाव और रिसाव को उन लोगों द्वारा अंजाम दिया जाता है जो हितलाभों के प्रवाह को नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं और तजुर्बे ने उन्हें सही साबित कर दिया है।

हमने आधार के कुछ अनिष्टसूचक पहलुओं की पड़ताल की थी जिसमें बिजनैस कॉरस्पोंडेंट मॉडल के संदर्भ में यह भी इंगित किया था कि यूपीए सरकार के तहत इस मॉडल को आकर्षक बनाने के लिए ''मुनाफे के लिए

(शेष पृष्ठ 2 पर)

मध्याह्न भोजन कर्मियों का विशाल प्रदर्शन

पटना (बिहार) : 19 सितम्बर को बिहार राज्य मध्याह्न भोजन कर्मी संघ के तत्वावधान में राज्य के मध्याह्न भोजन कर्मियों का प्रदर्शन मुख्यमंत्री कार्यालय के समक्ष हुआ। प्रदर्शन के लिए मध्याह्न भोजन कर्मियों का झंडे-बैनरों से सुसज्जित जुलूस गांधी मैदान से निकला; जो जे पी गोलम्बर, फ्रेजर रोड, डाक बंगला चौराहा, पटना जंक्शन गोलम्बर, न्यू मार्केट, मीठापुर होते हुए आर. ब्लॉक पहुंचा। जुलूस में शामिल मध्याह्न भोजन कर्मी 'मध्याह्न भोजन कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो' 'मध्याह्न भोजन कर्मियों को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी देनी होगी', 'प्रत्येक विद्यालय में हाजिरी रजिस्टर अनिवार्य करो', 'मध्याह्न भोजन कर्मियों को साल में कम-से-कम दो वर्दियां देनी होगी', 'मध्याह्न भोजन कर्मियों को सवेतन अवकाश देना होगा', 'मध्याह्न भोजन कर्मियों के वेतन का भुगतान बैंक खाते से करना होगा', 'मध्याह्न भोजन कर्मियों के साथ जातिगत भेद-भाव करना बंद करो', 'जातिगत भेद-भाव करने वालों को दंडित करो', 'कर्मियों को भोजन बनाने के अलावा अन्य सभी कार्यों से मुक्त रखो', 'बिना स्पष्टीकरण पूछे अनुशासनात्मक कार्रवाई करना बंद करो', 'प्रत्येक विद्यालय में आधुनिक रसोई घर का निर्माण करो',

'विद्यालयों में रसोई घर की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करो', 'अनुश्रवण कमिटी में मध्याह्न भोजन कर्मी संघ के प्रतिनिधियों को शामिल करो', 'शहरी क्षेत्र में एनजीओ द्वारा खाना बनवाना बंद करो' आदि नारे लगा रहे थे। (शेष पृष्ठ 4 पर)

सबके लिए बैंक खाता ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

कम्पनियों'' को बिजनैस कॉरस्पोंडेंटों के रूप में नियुक्त करने की इजाजत 2010 में भारतीय रिजर्व बैंक ने दी थी। लेकिन 'रिसाव' और छोड़ाव रोकना तो दूर रहा, असल में इस स्कीम ने भ्रष्टाचार का एक और द्वार खोल दिया। जैसा अक्सर देखा गया कि गाँव के मुखियाओं, सूदखोरों और खाद डीलरों ने खुद को बिजनैस कॉरस्पोंडेंटों के रूप में नामांकित कर लिया और दबंगई के बल पर हितलाभों को हड़प लिया। उस समय इकॉनोमिक टाइम्स द्वारा पंजाब से आई एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि ''75% बिजनैस कॉरस्पोंडेंट एजेण्ट गाँव के सरपंच या उनके सगे संबंधी हैं।'' मार्च 2011 में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के आंतरिक सर्कुलर में कहा गया था कि बिजनैस कोरस्पोंडेंटों को ''धांधलियों में लिप्त पाया गया है जैसे कि ग्राहकों से बैंक द्वारा अनुमोदित शुल्कों के अलावा अनधिकृत पैसे की मांग करना।'' सर्कुलर में बताया गया कि ''भोले भाले ग्राहकों'' का ''शोषण'' हो रहा है जो बैंक की साख को ''गम्भीर खतरे'' में डाल रहा है। इसके अलावा आरबीआई द्वारा किए गए हालिया सर्वे में खुलासा हुआ है कि असल में 47% बिजनैस कोरस्पोंडेंट ''लापता'' हैं। और फिर इस तथ्य को बताने की जरूरत नहीं है कि जब बेहद जरूरतमंद लोग बिजनैस कोरस्पोंडेंट को गाँव में उपस्थित नहीं पाते हैं लेकिन जब वे आते भी हैं तो पार्टेबल इलैक्ट्रोनिक गैजटों के ब्रेकडाऊन या इस या उस तरह की टैक्नीकल गड़बड़ी का सवाल खड़ा हो जाता है।

पूँजीवादी व्यवस्था बिचौलियों का उन्मूलन नहीं कर सकती है। तथाकथित बिजनैस कोरस्पोंडेंट और कुछ नहीं बल्कि बिचौलिये ही हैं एक खाता खोलने के लिए भी बैंक बिजनैस कोरस्पोंडेंट पर निर्भर रहेंगे। ये बिजनैस कोरस्पोंडेंट भी तभी प्रकट होंगे जब गरीब किसान या तो 5000 रु. का कर्ज लेंगे या दुर्घटना बीमा के लिए दावा पेश करेंगे। भ्रष्टाचार जब प्रशासन के साथ-साथ बैंकों और नियामक बॉडियों में प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त है, जिसकी खबरें प्रेस में आ रही हैं तो क्या गारण्टी है कि ऐसी चीजें प्रधानमंत्री जन-धन योजना में घटित नहीं होंगी?

बैंकों का फायदा ही फायदा

दूसरी तरफ यह बताया गया है कि कुछ बैंक नरेगा (ग्रामीण रोजगार योजना) के लिए आधार सक्षम सीधे कैश ट्रांसफर का इस्तेमाल खुद मुनाफा कमाने के लिए कर रहे हैं जिसमें वे इस उद्देश्य के लिए प्राप्त धन के बड़े हिस्से के वितरण को 45 दिन से लेकर तीन महीने तक रोके रखते हैं हालांकि यह नियमों के विरुद्ध है। क्या इसमें कोई आश्चर्य की बात है? आखिर भूमण्डलीकरण और उदारीकरण के सिद्धान्तों के अनुरूप बैंकों को कहा गया है कि वे वित्तीय समावेश को सामाजिक काम के नजरिए से नहीं बल्कि ''एक बिजनैस अवसर के रूप में'' देखें। यह दूसरी बात है कि इस तरह की देरी नरेगा कामगारों के लिए अकथनीय मुश्किलों का सबब बनती है जिन्हें अपनी मजदूरी की जबरदस्त दरकार होती है।

क्या यह मान लेने का कोई कारण है कि आज भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और धांधलियाँ बेहद बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत क्या इन बातों में बहुत सुधार हो जाएगा और लोगों का बहुत भला होगा? उल्टे यह सर्वविदित है कि पूँजीवादी व्यवस्था जो बहुत पहले ही जीर्ण-शीर्ण और असमाधेय रूप से बीमार और भ्रष्ट हो गई है। मुफ्तखोरों को पनपाती है जो इस शोषणमूलक व्यवस्था के कल-पुर्जे बन गए हैं जहाँ वंचना और हड़पना या उत्पीड़ित बहुसंख्यक जनता के जायज किसी पावने को हजम कर लेना दस्तूर बन गया है। बहुत बड़ी तादाद में अभागे गरीबों की कमरतोड़ तकलीफों और अज्ञानता का फायदा उठा कर आम आदमी के लिए दिए जाने वाले हितलाभों का बड़ा हिस्सा नितांत भ्रष्ट प्रशासन की सांठ गांठ की वजह से इस या उस रूप में ऐसे छोड़ाव और रिसाव का बेरोकटोक शिकार हो रहा है। इसलिए मौजूदा व्यवस्था द्वारा पनपाई जा रही इन बुराइयों से उत्पीड़ित जनता को प्रधानमंत्री जन-धन योजना कैसे निजात दिला पाएगी? और किस तरह का वित्तीय समावेश उनको हासिल होगा?

5000 रु. की कर्ज सुविधा कैसे प्रभावकारी होगी?

गरीब के लिए कर्ज के बारे में क्या? यह बताया गया है कि 5000 रु. के ओवर ड्राफ्ट या कर्ज की सुविधा आधार सक्षम खातों पर 6 महीने के बाद उपलब्ध होगी यदि इस दौरान तसल्लीबख्श लेन-देन के माध्यम से खाता धारक अपनी कर्ज पात्रता सिद्ध कर देता है। सिर्फ रु. 5000 का कर्ज? सिर्फ 5000 रु. से क्या होगा? इसके अलावा जब गरीब कर्ज लेने का प्रयास करते हैं तो उनके साथ क्या गुजरती है? एक जाने माने पत्रकार पी. साईनाथ के हवाले से द *हिन्दू* में छपी एक रिपोर्ट का ही उदाहरण ले लें। पिछड़े हुए मराठवाड़ा में उन्होंने पाया कि एसबीआई ने व्यापारियों को 150 मर्सीडीज बैंज कारें खरीदने के लिए 7% ब्याज दर पर कर्ज मुहैया कराने में तत्परता दिखाई, जबकि 7% ब्याज दर पर कर्ज लेने से पहले किसानों को वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा और वह भी सिर्फ थियोरी में ही रहा। जो उन्होंने पाया वह था: ''एक मर्सीडीज खरीदो तो 7% ब्याज दो। एक ट्रेक्टर खरीदो तो 12% ब्याज दो।'' और जब कर्जों की अदायगी की बात आती है तो भेदभाव और भी साफ उजागर हो जाता है। जहाँ बड़े कोरपोरेट घराने करोड़ों रुपये की कर्ज देनदारी से साफ बच निकलते हैं वहीं आम लोग जो घटती आमदनी या कुछ आकस्मिक वजहों से कर्ज वापसी में घोर कठिनाइयों का सामना करते हैं, अगर वे देनदारी में चूक करते हैं तो उन्हें प्रताड़ित किया जाता है और गंभीर परिणाम भुगतने तक की धमकी दी जाती है। ऐसे ही हथकण्डों से भारी पैमाने पर फसल बर्बाद होने से पीड़ित और बैंक कर्जों की देनदारी में चूक की वजह से हताश होकर बड़ी संख्या में किसान आत्म हत्या करने को मजबूर हुए हैं। कुछ मामलों में रिकवरी एजेण्ट देनदारी में चूक करने वालों को न सिर्फ शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करते हैं बल्कि उनकी जमीन और किसी अन्य अचल सम्पत्ति को कर्ज वसूली के लिए जब्त कर लेते हैं। (जिसकी कीमत कर्ज से कहीं ज्यादा होती है।) हाल ही में एक घटना प्रकाश में आई है कि कैसे एक बिजनैस कोरस्पोंडेंट या ग्रामीण दलाल ने यू.पी. के एक गांव में अनोखे तरीके से किसानों को ठगा है। उसने 5000 रुपये के पशु कर्ज के लिए किसानों से फार्मों पर 'हस्ताक्षर' करवा लिए। उन फार्मों के साथ साथ उसने किसानों से धन निकासी पर्ची पर भी अंगूठे के निशान लगवा लिए फिर बैंक मैनेजर से सांठगांठ करके उसने कर्ज के आंकड़े को 5 लाख रुपये कर दिया और बिना किन्ही दस्तावेजों के लोन मंजूर करवा लिया, धन निकासी पर्ची की मदद से लोन निकाल लिया और फिर चम्पत हो गया। किसानों की पास बुकों में कर्जों की मंजूरी और भुगतान दर्शाया गया। किसानों को चार साल बाद पता चला कि उनसे धोखा हुआ है, इससे भी बड़ी बात है कि उन कर्जों की अदायगी के लिए उन्हें अपने घर-बार से हाथ धोना पड़ा जो कर्जे उन्होंने कभी लिए ही नहीं थे। क्या गारण्टी है कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत ऐसी घटनाएं नहीं घटेंगी। जहाँ व्यवस्था में भ्रष्टाचार गहरे पैठ गया है और कानून की किताब में ऐसी धांधलियों का कोई निराकरण नहीं है।

दुर्घटना बीमा पर

जैसा कि उल्लेख किया गया है प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत दुर्घटना बीमा के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। किसको बीमा मिलेगा? ऐसी दुर्घटना बीमा सुविधा बहुत से बैंकिंग उत्पादों, क्रेडिट कार्डों इत्यादि पर उपलब्ध हैं। ऐसे कर्जों के दावे और निपटारे का ट्रेक रिकार्ड क्या है? बीमा के लिए कैश ट्रांसफर होने से पहले सम्बंधित दस्तावेज 'बेरहम अफसरशाही' के हाथों से गुजरते हैं और मंजूरी उनके द्वारा दी जाती है। संबंधित दस्तावेजों के साथ एक दुर्घटना को सिद्ध करना अगर असंभव न भी हो, पर बहुत ही मुश्किल जरूर है। यह सोच कर ही कंपकपी छूटती है कि बहुसंख्यक गरीबों, अर्धशिक्षित और अशिक्षित लोगों में जगाई गई उम्मीदों और अपेक्षाओं का क्या अंजाम होगा जिनके लिए वंचना ही नियम है यहाँ-वहाँ कुछ अपवादों को छोड़कर! कैसे अफसरशाहों या अधिकारियों को किसी भी स्कीम में दावेदारों की संख्या को कम रखने का काम सौंपा जाता है जिसे वे बखूबी करते हैं। इसको कुछ वर्षों पहले पी. साईनाथ द्वारा लिखी एक खोजी रिपोर्ट द्वारा उजागर किया गया था (द *हिन्दू* में छपी थी) जो महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्याओं के बारे में थी। कैसे बने एक 'उपयुक्त आत्महत्या' यह रिपोर्ट स्पष्ट रूप से एक उदाहरण प्रस्तुत करती है कि कैसे अफसरशाही आसानी से ऐसा घृणित काम कर सकती है जैसा कि इन्होंने महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्याओं की संख्या कम करने के लिए किया है। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने इस तरीके से सरकारी दस्तावेजों को बनाया कि कॉलम के बाद कॉलम में वे आंकड़ों को काट-छांट सकते हैं कि निर्धारित शर्तें पूरी नहीं की गई जब तक कि अंतत: कर्ज या विपत्ति की वजह से आत्महत्या की तरफ धकेल दिए गए किसानों की असल संख्या के आंकड़े12% तक नहीं पहुँच जाते हैं। जिन्हें 'उपयुक्त' या 'असल' आत्महत्या माना जाता है। इसका मायना है कि असल में बहुत कम किसान परिवार ही जिन्होंने आत्महत्या की वजह से रोटी जुटाने वाले को खो दिया है, सरकार से मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। क्या यह यकीन करने का कोई कारण है कि बहुसंख्यक गरीब जब एक लाख रुपये के दुर्घटना बीमे का दावा करेंगे तो उनके साथ सही सलूक होगा? उनमें से वे चन्द भाग्यशाली जिनका दावा मंजूर किया जाएगा–क्या यह स्वत: सिद्ध होगा कि वास्तव में ही वे सीधे कैश ट्रांसफर के जरिये असल हितलाभ प्राप्त कर सकेंगे?

किस तरह का वित्तीय समावेश

अत: हमारे देश में बहुसंख्यक गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जन-धन योजना किस तरह का वित्तीय समावेश प्रदान करेगी जो भूख और कुपोषण के मामले में उप-सहाराई अफ्रीका से भी पीछे है जहाँ यह बहुप्रचारित विकास का मॉडल–गुजरात –'इण्डिया स्टेट हंगर इण्डेक्स 2008' में भारत के 17 बड़े राज्यों में से 13वें स्थान पर है? ऐसी एक स्थिति में जहाँ झुग्गी बस्तियाँ (स्लम्स) जो पूँजीवाद के रिसते शहरी घाव हैं जिन्हें जब विदेशी गणमान्य व्यक्ति दौरे पर आते हैं तो पर्दे के पीछे छिपाना पड़ता है –जैसा कि चीनी प्रधानमंत्री के दौरे के समय अहमदाबाद में साबरमती आश्रम को जाने वाले रोड पर हकीकत में ऐसा हुआ या दिल्ली में राष्ट्रमण्डल खेलों के मामले में इन्हें नजर से दूर रखने के लिए बैरीकेड लगाए गए थे–उनके लिए ''वित्तीय समावेश'' का असल मायने क्या है जिनकी स्थिति को पर्दे के पीछे छिपाने की जरूरत पड़ती है? और ग्रामीण क्षेत्रों में रिसते घावों के बारे में तो जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा है। जब गुजरात में आबादी के लगभग 18% हिस्से को ही सिर्फ तीन मूलभूत सेवाओं की एक साथ उपलब्धता है जैसे पीने का पानी, बिजली और साफ-सफाई और समाज के निचले तबके के लागों को उच्च वर्गों के हाथों निर्मम दमन-अत्याचार का शिकार होना पड़ता है।

निश्चित ही इसका मायना यह नहीं है कि बहुसंख्यक गरीबों को बैंकिंग सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए और वे बेईमान पोंजी स्कीमों, माइक्रोफाइनेन्स, सूदखोरों इत्यादि के रहमों करम पर रहें। लेकिन जिसका वायदा किया गया है और इस स्कीम के माध्यम से जो मुहैया कराया जाएगा उसमें जमीन आसमान का अन्तर है जो सिर्फ छलावे के सिवाय और कुछ नहीं है। इसके अलावा यह कहने की जरूरत नहीं है कि अधिकतर गरीबों को जीवन यापन के लाले पड़े हुए हैं। किफायत और बचत की तो बात ही छोड़ दीजिए लेकिन प्रयास है कि गरीबों से ऊपर के तबके के पास जो भी थोड़ा बहुत पैसा है उसे बैंकिग सिस्टम में मिलाया जाए और इस प्रकार बैंकों की पूँजी को बढ़ाया जाए।

लेकिन इसका एक और भी पहलू है। यूपीए सरकार का अनुसरण करते हुए मोदी सरकार जिसने रसोई गैस सब्सिडियों और खाद्य सब्सिडियो को खत्म करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया है, यह भी चाहती है कि रसोई गैस सब्सिडी और पीडीएस सहित उर्वरकों इत्यादि के लिए सब्सिडी प्रधानमंत्री जन-धन योजना के हिस्से के रूप में सीधे कैश ट्रांसफर स्कीम के जरिये दी जाए और वह भी आधार से जोड़ कर। यह भी स्मरण रहे कि यह डीबीटी स्कीम बिजनेस कॉरस्पोंडेंट स्तर पर लाभार्थियों को प्रमाणीकृत करने के लिए इस्तेमाल की जा रही बायोमैट्रिक टैक्नोलॉजी के वजह से फेल हो गई जिसमें उच्च गड़बड़ी रेट दर्ज किए गए हैं जो कभी कभी 25-30% तक पहँच जाती है। इसके अलावा इसने आलोचना का तूफान खड़ा कर दिया है और इसे लागू करने की बाध्यता की वजह से नागरिक ग्रुपों से तीव्र प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है। पहली आशंका यह जाहिर हो गई है कि इसके चलते सब्सिडियाँ पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी और दूसरी *आधार* से सम्बंधित है। इसके सुरक्षा पहलुओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे। खासकर निजता पर अतिक्रमणकारी हमले द्वारा निजता के उल्लंघन को आसान बना दिए जाने के डर से, जिसकी वजह से जनवादी आन्दोलन के कार्यकर्ताओं के साम्प्रदायिक धार्मिक और राजनैतिक गतिविधियों का खाका खींचना और भी आसान हो जाएगा।

इस तरह, बहुप्रचारित गरीबों के वित्तीय समावेश से आखिर किसको फायदा होने वाला है, मेहनतकश जनता को या मोदी सरकार को जो इससे राजनैतिक लाभ उठाने की फिराक में है, संकटग्रस्त पूंजीवाद के बोझ को भविष्य में मेहनतकश जनता के कंधों पर डालने के लिए जो इसे कुछ और कठोर कदम उठाने में सक्षम बनाने के लिए है? इसलिए आज गरीबों की जरूरत क्या है? असल में उन्हें जरूरत है गरीबी दूर करने, बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने, लाभकारी स्थायी रोजगार देने, कृषि में लागत खर्च कम करने और बिचौलियों के हस्तक्षेप मुक्त कृषि पैदावार के लाभकारी मूल्य प्रदान करने की। लोगों को ऐसे बैंक खाते के चमकदमक वाले अधिकार की नहीं बल्कि जीवनयापन के साधनों की जरूरत है। ●●

आदर्शगत स्तर को उन्नत करते हुए खुद को हमेशा क्रांतिकारी भावना-धारणा से ओत-प्रोत रखना होगा

5 अगस्त असम की सभा में कॉ. असित भट्टाचार्य

(एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के संस्थापक महासचिव, इस युग के अन्यतम श्रेष्ठ मार्क्सवादी दार्शनिक, कॉमरेड शिवदास घोष के 38वें स्मृति दिवस पर असम राज्य कमेटी द्वारा 5 अगस्त को गुवाहाटी के लक्ष्मीराम बरूआ सदन मे एक जनसभा का आयोजन किया गया। सभा के मुख्य वक्ता थे पार्टी के पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉ. असित भट्टाचार्य। सभा की अध्यक्षता राज्य सचिव कॉ. चन्द्रलेखा दास ने की।)

सभापति के भाषण में कॉ. चंद्रलेखा दास ने सर्वहारा के महान नेता कॉ. शिवदास घोष के प्रति श्रद्धांजली देते हुए उनकी मूल शिक्षा को याद किया और राज्य की कठिन राजनैतिक परिस्थिति की व्याख्या की।

मुख्य वक्ता कॉ. असित भट्टाचार्य ने कहा कि शुरू में ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज के दिन जो प्रासंगिक पहलू हैं उनको जिस तरह रखना जरूरी था अस्वस्थ्य होने की वजह से उतना समय लेकर यह काम मैं नहीं कर सकूंगा, फिर भी बहुत जरूरी कुछ बातों का उल्लेख करने का प्रयास करूंगा।

इतिहास के गतिपथ पर सशक्त पदचिन्ह छोड़ते हुए एक बिरले चरित्र के अधिकारी हुए थे कॉ. शिवदास घोष। अपनी अंतिम सांस तक इस महान चिंतनकार ने मार्क्सवाद-लेनिनवाद के महान आदर्श को हमारे अंदर स्थापित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। हमें नए जीवन की उपलब्धि हुई, नई रोशनी का पता चला। इस शोक की गंभीरता इतनी है कि मैं 5 अगस्त 1976 और आज 5 अगस्त 2014 के बीच कोई फर्क नहीं खोज पाता हूँ। साथ ही 'अपनी पीड़ा को दृढ़निश्चय में परिणत करो'– लेनिन की उस बात को याद करता हूँ, याद करता हूँ सर्वहारा के महान नेता कॉ. शिवदास घोष की अमर शिक्षा–'जितना गहरा शोक, क्रांतिकारी के लिए उतना ही गहरा कर्तव्यबोध, गहरे शोक से ही अत्यंत गहरा कर्तव्यबोध जन्म लेता है।' इसलिए उनका मृत्यु दिवस पार्टी जीवन में सबसे शोकमय दिन है। आज वे शारीरिक रूप से हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, जिस तरह महान मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन, माओ-त्से-तुंग नहीं हैं। लेकिन फिर भी इन महान व्यक्तियों की चिंतनधारा जिस प्रकार प्रतिदिन निःसंदेह दुनिया के दबे-पिसे, शोषित-उत्पीड़ित जनसाधारण का एकमात्र सम्बल है, ठीक उसी प्रकार कॉ. शिवदास घोष की चिंतनधारा भी न केवल भारत के शोषित-उत्पीड़ित लोगों को रास्ता दिखा रही है बल्कि पूरी दुनिया के शोषित-उत्पीड़ित लोगों के सामने एक मार्गदर्शन के तौर पर काम कर रही है। महान मार्क्स का जो सिद्धांत मजदूर वर्ग की शोषण से मुक्ति के हथियार के रूप में पूरी दुनिया के सामने उभर कर आया था, वह जिस प्रकार हमेशा विकासशील है, ठीक उसी प्रकार कॉ. शिवदास घोष की चिंतनधारा भी उसी धारावाहिकता में उत्पन्न एक उन्नत धारा है। हम देख रहे हैं कि मार्क्सवाद-लेनिनवाद को समृद्ध करने के रास्ते कॉ. शिवदास घोष जो सर्वोत्तम समझदारी देकर गए हैं वह हर दिन लोगों को प्रभावित करती जा रही है, शोषित लोग मुक्ति की दिशा ढूंढ़ पा रहे हैं। ठीक है आज के इस खास दिन हम उनकी शिक्षाओं के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं लेकिन कॉ. घोष की शिक्षा और चिंतनधारा एक ऐसा हथियार है जिसको हर दिन जनसाधारण के सामने प्रस्तुत करने का काम भी हम लगातार करते जा रहे हैं ताकि मेहनतकश जनता का मुक्ति संघर्ष तीव्रतर हो और भारत का क्रांतिकारी आंदोलन सही रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ता जाये। हम पूरी तरह से सचेत ढंग से इस ऐतिहासिक कर्तव्य को सही-सही पालन नहीं कर पाए तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। यह कहने की जरूरत नहीं है कि 5 अगस्त मनाना कोई औपचारिकता नहीं है। आज का दिन उनके द्वारा दी गई मार्क्सवाद-लेनिनवाद की सर्वोन्नत समझदारी को ग्रहण करके और भी ताकतवर बनने और असीम निष्ठा के साथ उसे क्रियान्वित करने के लिए पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और जनसाधारण को एक साथ मिलकर बार-बार संकल्पबद्ध होने का दिन है।

उनके चिंतन की रोशनी में राष्ट्रीय-अतर्राष्ट्रीय आर्थिक, राजनैतिक परिस्थिति को अति संक्षेप में विश्लेषण करते हुए मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि जिस मौजूदा कठिन परिस्थिति के दौर से दुनिया गुजर रही है उसको सही-सही जानने-समझने की जरूरत है। क्योंकि राष्ट्रीय-अतर्राष्ट्रीय परिस्थिति की वास्तविक समझदारी के बिना हम अपने ऐतिहासिक कर्तव्य को निर्धारित नहीं कर पाएंगे। आप देख रहे हैं कि उत्तरी कोरिया और क्यूबा इन दोनों देशों को छोड़कर सारी दुनिया आज पूंजीवाद के शिंकजे में है। पूरी दुनिया में ही आज पूंजीवाद का तांडव चल रहा है। यह पूंजीवाद आज और अपने विकास के युग में नहीं है। आज यह पतनशील पूंजीवाद है, जिसने दुनिया में सभी जगह निकृष्ट साम्राज्यवाद का रूप धारण कर लिया है। साथ ही साथ आज इसने तमाम जनतांत्रिक मूल्यबोधों को तिलांजलि देकर फासीवाद का चरित्र अख्तियार कर लिया है। कॉ. शिवदास घोष सरल भाषा में हमें यह दिखा गए हैं।

प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध की बात आप जानते हैं। नाम के वास्ते तीसरा विश्वयुद्ध अभी भी नहीं हुआ है। लेकिन पूरी दुनिया में जो चल रहा है वह तीसरे महायुद्ध का ही दूसरा नाम है। दुनिया का प्रत्येक देश आज युद्ध क्षेत्र में है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका जिस तरफ भी नजर दौड़ाइये सभी देशों में किसी न किसी तरह से युद्ध चल रहा है। किसी-किसी क्षेत्र में एक देश के साथ दूसरे देश का सामरिक अथवा आर्थिक युद्ध चलने पर भी इन सब युद्धों का प्रथम या द्वितीय विश्वयुद्ध के साथ एक मौलिक तफर्का है। प्रथम या द्वितीय विश्वयुद्ध में जिस प्रकार एक देश के खिलाफ दूसरे देश का युद्ध हुआ था, पूरी दुनिया किसी न किसी तरह से इस युद्ध में शामिल हो गई थी, मौजूदा परिस्थिति में सभी मामलों में ऐसा नहीं है। इस युद्ध या युद्ध के जैसे संघर्षों में ज्यादातर ही जनता बनाम जनता का संहारक युद्ध है। जनता का एक भाग पूंजीवादी-साम्राज्यवादी ताकतों और उनकी ताबेदार पार्टियों की साजिश के जाल में फंसा है, उनकी अति धूर्त उकसावेबाजी का शिकार हो रहा है। जनता का एक हिस्सा इसके चलते दूसरे एक हिस्से पर टूट पड़ रहा है, वीभत्स हत्याकांड में लिप्त हो रहा है। जनता के साथ जनता के इस युद्ध संघर्ष का खात्मा नहीं हो रहा इतना ही नहीं बल्कि पूंजीवादियों-साम्राज्यवादियों के उकसावे से इसका दायरा भी बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ यह भी पकड़ में आ रहा है कि अंतिम विचार में जनता बनाम जनता के इस युद्ध में ऐसा नहीं है कि कोई आपरेटर या चालक नहीं है, पूंजीपति और उनकी ताबेदार पार्टियां ही दुनिया में सभी जगह इस भ्रातृघाती संघर्ष और हत्याकांड के मूल आपरेटर या चालक हैं। स्पष्ट है कि ये सब युद्ध पूंजीवाद-साम्राज्यवाद को शत्रु निर्धारित कर उसके शोषण से मुक्ति का लक्ष्य लेकर संचालित नहीं हो रहे हैं। बल्कि इन सब के परिणाम स्वरूप साम्राज्यवादियों की नींव विभिन्न देशों में और भी मजबूत होती जा रही हैं। पूंजीपति वर्ग के जघन्य षड्यंत्र को सही-सही समझने और इस षड्यंत्र के जाल से खुद को बाहर निकाल लाने में सक्षम मतादर्श भी आज इनके सामने नहीं है। इसीलिए एक तरफ आत्मघाती युद्ध-संघर्ष और दूसरी तरफ पूंजीपति वर्ग के चौतरफा शोषण की वजह से हजारों लाखों लोग कुत्ते-बिल्लियों की तरह खामख्वाह मारे जा रहे हैं। इस हमले से मुक्त रहकर गुजर बसर कर पा रहा हो ऐसा कोई भी देश नहीं है। अतः पूरी

सभा को संबोधित करते हुए कॉ. असित भट्टाचार्य

दुनिया में ये जो युद्धमय हालात हैं इनकी जड़ पूंजीवाद और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर निहित है। पूंजीवादी-साम्राज्यवादियों के मुनाफे का स्वार्थ ही यहां मूल कारण है, आर्थिक मामला ही सब कुछ तय करता है, इन सबसे यह एक बार फिर सुस्पष्ट हो गया है।

राष्ट्रीय परिस्थिति के क्षेत्र में भी कोई तफर्का नहीं है, भारत में भी आज वही तस्वीर दिखाई दे रही है। जनता बनाम जनता का युद्ध। असम में क्या देखा जा रहा है? असमिया-गैर असमिया का झगड़ा, बोडो-गैर बोड़ो के बीच झगड़ा, राभा-गैरराभा का द्वंद्व-संघर्ष – लगातार खूरेंजी। इस समय एक गरीब राभा एक गरीब मुसलमान को देखने से ही मार देना चाहता है। जो मार रहा है और जो मर रहा है दोनों ही शोषित वर्ग से हैं। फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, यही तो हो रहा है। पूरे देश में ही आज यह रक्तरंजित साम्प्रदायिक झगड़ा प्रकट हो उठा है। यह सुनिश्चित करने के लिए ही कि रूसी क्रांति, चीनी क्रांति की तरह किसी सशस्त्र क्रांति का सामना न करना पड़े, पूंजीपति आज जीजान से चेष्टा कर रहे हैं, तरह-तरह के छल-कपट का सहारा ले रहे हैं, लोगों को आत्मघाती रास्ते पर धकेल देने के लिए नित नए-नये तरीके खोज रहे हैं। इसीलिए इस परिस्थिति में यह स्पष्ट है कि पूंजीपति वर्ग के इस षड्यंत्र, इस रणकौशल को नाकाम कर देना होगा। इसके सिवाय इस परिस्थिति का मुकाबला करने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। साथ ही साथ यह भी ध्रुव सत्य है कि यह शक्ति जनसाधारण में है। शोषित जनता अगर सही मायने में एकजुट होकर, शक्तिशाली होकर खड़ी हो जाये तो पांच मिनट भी सत्ता में बने रहने का दुनिया के किसी भी देश के पूंजीपति वर्ग, साम्राज्यवादियों का सामर्थ्य नहीं है। आप लोगों ने खुद ही देखा है कि पिछले कुछ वर्षों में एशिया और अफ्रीका के देशों में अल्पस्थाई जन-अभ्युत्थान के माध्यम से जनता ने अपने देश के अत्याचारी शासकों को बड़ी आसानी से सत्ता से उखाड़ फेंका था। हालांकि यह भी सत्य है कि सही सिद्धांत के आधार पर संगठित होकर इस तरह काम किये बिना वांछित लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। नया हथकण्डा अपना कर पूंजीपतियों के वही ताबेदार अलग जामा पहनकर सत्ता में फिर लौट आए।

सवाल है कि जनता को यह शक्ति, यह सैद्धांतिक ज्ञान जुटाएगा कौन? इस 'कौन' का मतलब कोई व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि एक विचारधारा है। आज के दिन वह विचारधारा है विज्ञान पर आधारित मार्क्सवाद-लेनिनवाद यानी द्वंद्वात्मक वस्तुवाद। दुनिया के शोषित-उत्पीड़ित लोगों के हाथ में मार्क्सवाद एक अपराजेय वैचारिक सिद्धांत है। यह मार्क्सवाद-लेनिनवाद यानी द्वंद्वात्मक वस्तुवाद जिसे एंगेल्स-लेनिन-स्टालिन-माओ त्से-तुंग

(शेष पृष्ठ 4 पर)

कॉ. असित भट्टाचार्य का भाषण...

(पृष्ठ 3 का शेष)

और कॉ. शिवदास घोष सभी ने और भी समृद्ध किया है, उनके चिंतन को सही-सही तरीके से समझने और समझाने का संघर्ष तीव्रतर करना ही इस कठिन परिस्थिति में ऐतिहासिक जरूरत है। लेकिन खुद के अंदर समझने का संघर्ष सही-सही तरीके से सम्पन्न हुए बिना यह कार्य आगे नहीं बढ़ सकेगा, क्रांति नहीं हो सकेगी। क्रांति का मायने ही है फिलहाल मौजूद एक स्थिति का आमूल परिवर्तन। हम यदि मार्क्सवाद-लेनिनवाद-कॉमरेड शिवदास घोष की चिंतनधारा के आधार पर स्थिति का मुकाबला न कर सके तो परिस्थिति और भी भयावह हो जाएगी। इसलिए क्रांति निर्भर करती है क्रांति के असल सिद्धांत को सही तरीके से समझने पर। मार्क्स की धारा में लेनिन ने कहा था इतिहास के गतिपथ पर क्रांति अप्रतिरोध्य है। क्रांति की वास्तविक स्थिति तैयार है सिर्फ धाय की जरूरत है। कौन है वह धाय? वह है मार्क्सवाद-लेनिनवाद-कॉ. शिवदास घोष की चिंतनधारा से लैस क्रांतिकारी राजनैतिक पार्टी। प्रत्येक क्रांतिकारी को ही मार्क्सवाद-लेनिनवाद की इस विचारधारा का ज्वलंत प्रतीक बन जाने के संघर्ष में लग जाना होगा, जिससे शोषित-उत्पीड़ित जनता को चुम्बक की तरह आकर्षित करने की क्षमता पैदा होगी। मार्क्सवाद-लेनिनवाद की समझ हासिल करने के इस संघर्ष के जरिए एक-एक दो-दो करके असंख्य क्रांतिकारी पैदा होंगे, जिनके चरित्र में 'क्रांति ही जीवन' यह साकार हो उठेगा। सबसे पहले खुद के अंदर की तमाम मलिनता, आत्मकेन्द्रिकता दूर करके, निरंतर प्रक्रिया में खुद को साफ-सुथरा, परिष्कृत करके, व्यक्तिगत सम्पत्तिबोध से खुद को मुक्त करके, व्यक्तिवाद के अवशेष तक भी जड़ से मिटाकर ये क्रांतिकारी जनता के बीच जाएंगे, जनता को संगठित करेंगे और जनता के संघर्ष को सही रास्ते पर संचालित करने के संग्राम में जुट जाएंगे। क्रांति और क्रांतिकारी जीवन से अलग कोई अस्तित्व उनका नहीं रहेगा। इसी रास्ते से क्रांति होगी।

दूसरा पहलू है क्रांतिकारी पार्टी। लेनिन ने बार-बार याद दिलाया था कि क्रांतिकारी पार्टी के बिना क्रांति नहीं हो सकती है और सही क्रांतिकारी सिद्धांत के बिना क्रांतिकारी पार्टी गठित नहीं हो सकती है। इसलिए अभ्रांत और सही क्रांतिकारी सिद्धांत की जरूरत है। सही समझदारी के आधार पर सही क्रांतिकारी पार्टी बनाने की जरूरत है। उच्चतर संग्राम की शुरूआत करते हुए प्रत्येक क्रांतिकारी कार्यकर्ता को और भी शक्तिशाली बनने की जरूरत है। इसी तरीके से एक व्यक्ति श्रेष्ठ क्रांतिकारी के रूप में विकसित होगा और इस प्रकार सैद्धांतिक सांगठनिक संघर्ष निर्मित करते हुए अत्यंत क्षमतावान, अत्यंत जुझारू क्रांतिकारी के रूप में खुद को ढाल लेगा। इस तरह खुद को निर्मित करने का संघर्ष ही है क्रांतिकारी पार्टी को मजबूत करना। यह काम क्रांति के बाद के समय में सही तरीके से न होने की वजह से ही रूस में, चीन में समस्या पैदा हुई थी। लेनिन-स्टालिन के बाद सोवियत यूनियन में, माओ-त्से-तुंग के बाद चीन में जिन नेता-कार्यकर्ताओं पर जिम्मेदारी आयद हुई थी वे अपनी सही ऐतिहासिक भूमिका नहीं निभा सके थे। चिंतन-चेतना का स्तर ऊपर उठने की बजाए इसमें गिरावट आ गई थी, जाने-अनजाने उनमें से बहुत से पूंजीवादी चिंतन-भावना का शिकार होते गए। इसी के अनिवार्य परिणामस्वरूप लेनिन-स्टालिन-माओ त्से-तुंग की अपूर्व अनुपम रचना जिसने सारी दुनिया को चौंका दिया था, विस्मित कर दिया था वह अति अल्प समय में ही धराशायी हो गई। तमाम विश्व ब्रह्मांड ही नियम के अधीन है, नियम के द्वारा ही संचालित है। नियम और पद्धति के उल्लंघन का अंजाम आगे आयेगा ही—इस घटना के जरिये एकबार फिर यही साबित हुआ है।

कॉमरेड शिवदास घोष जो पार्टी बनाकर गए हैं उसकी रक्षा करने और भारत की क्रांति को आगे बढ़ाने के सवाल पर भी इस विषय की समझदारी हासिल करना सबसे पहले जरूरी है। मैं दृढ़तापूर्वक कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी की रक्षा करना और विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन की रक्षा करना एक जैसा ही काम है। क्योंकि मार्क्सवाद-लेनिनवाद की जो सर्वोच्च समझ कॉमरेड शिवदास घोष से हमें मिली है उसकी वास्तविक समझ के बिना भारत में तथा दुनिया में आज सही कम्युनिस्ट आंदोलन को आगे बढ़ाना कतई संभव नहीं है। हिस्टोरिकल रोल ऑफ इंडिविजुअल या व्यक्ति की ऐतिहासिक भूमिका की धारणा की जो समृद्ध समझदारी उन्होंने पैदा की, उसकी सही-सही समझदारी क्रांति चाहने वाले सभी लोगों के लिए जरूरी है। आज दुनिया में जो परिस्थिति पैदा हुई है, पूंजीपति वर्ग जनता को भ्रमित करने के लिए जिस जघन्य कौशल का सहारा ले रहा है और क्रांति को लगभग असंभव बना देने का प्रयास कर रहा है उसको रोक देने के लिए, उसको परास्त कर देने के लिए मार्क्सवाद-लेनिनवाद की समझ को बहुत ऊपर ले जाना होगा। इसके जरिए ही न केवल विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन जड़ता से मुक्त होगा बल्कि तेजी से ताकतवर और वेगवान भी होगा। इस संघर्ष में कॉमरेड शिवदास घोष के चिंतन को आत्मसात करने के लिए सटीक चर्चा और व्यक्तिगत जीवन में तथा क्रांतिकारी आंदोलन संचालित करने में उसका सटीक प्रयोग भी अपरिहार्य है, कितनी तेजी से हम अपने अंदर की सारी मलिनता दूर करके सैद्धांतिक ज्ञान को प्रतिदिन परखने में सक्षम होंगे, उनके पुरजोर आह्वान पर प्रत्युत्तर देते हुए जीवन के तमाम पहलुओं को समेटते हुए असली कम्युनिस्ट चरित्र निर्मित करने के संघर्ष में जुटेंगे, उसी पर एसयूसीआई(सी) पार्टी की ताकत में बढ़ोतरी निर्भर करेगी। इसी रास्ते भारत की क्रांति का मार्ग प्रशस्त होगा और विश्व क्रांति का संघर्ष भी आगे बढ़ेगा। विश्व साम्यवादी आंदोलन को नई शक्ति से शक्तिमान कर डालने और भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को तेजी से आगे बढ़ाने का सवाल, एसयूसीआई(सी) के तेजी से विकास और प्रगति को सरअंजाम देने का सवाल किस तरह कॉमरेड शिवदास घोष हरेक कार्यकर्ता को क्रांति के लिए हानिकारक चिंतन भावना कार्यकलाप से मुक्त करने के लिए असाधारण संघर्ष कर गये हैं उसे हमें रोजाना याद करना होगा। पूंजीवाद की भूमिका निःशेषित हो गई है इसलिए आज क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं पर वह कोई असर डालने में सक्षम नहीं है —यह बात सच नहीं है बल्कि सच तो यह है कि चुपचाप पिछले दरवाजे से उपयुक्त क्रांतिकारी चेतना की गैरमौजूदगी का फायदा उठाकर पूंजीवाद उनमें से अनेक को विपथगामी बना देने की क्षमता रखता है। इसीलिए हमें अवश्य ही इस बात पर प्रखर नजर रखनी होगी कि पार्टी के अंदर गैर क्रांतिकारी कोई भी ट्रैट्स, ट्रेंड्स और टेंडेंसी (रुझान) अति सूक्ष्म रूप में होने पर भी सिर उठा रहा है कि नहीं। लगातार हर कार्यकर्ता आत्मनिरीक्षण जारी रखे। नेताओं का अन्यतम प्रधान कर्तव्य होगा- क्लेन्डेस्टाइन इन्फेस्टेशन ऑफ बुर्जुआ थोट(पूंजीवादी चिन्तन के गुप्त प्रहार)को अंकुर में ही ध्वस्त कर डालना, बुर्जुआ ध्यान-धारणा से ग्रस्त कार्यकर्ताओं को जल्द से जल्द इस समस्या से मुक्त करने के लिए हर तरह की व्यवस्था लेना। अवश्य ही याद रखें पूंजीवाद एक बहती हुई जहरीली हवा है। वैचारिक स्तर उन्नत कर प्रतिदिन खुद को क्रांतिकारी विचारधारा से लैस किये बिना, उससे छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है। चाहे कार्यकर्ता हो या नेता, उपयुक्त प्रतिरोध क्षमता की कमी रहने से पूंजीवाद किसी को बख्शता नहीं है। आज 5 अगस्त इस महान चिंतनकार के स्मृति दिवस पर इस सवाल पर उनके संघर्ष की धारा में हम मिलकर यह शपथ लें कि चोर रास्ते से तर्क का जामा पहन कर हमें पथभ्रष्ट कर लक्ष्य से भटकाने की साजिश को हम सफल नहीं होने देंगे। लगातार उनकी शिक्षाओं द्वारा संचालित चौतरफा संघर्ष चलाते हुए इस साजिश को हम नाकाम कर देंगे। व्यक्तिगत सम्पत्ति, सम्पत्तिबोध, व्यक्तिवाद, सूक्ष्मातिसूक्ष्म व्यक्तिकेन्द्रित चिंतन की आखिरी जड़ को हम उखाड़ फेकेंगे। हम होंगे अपने जागरूक प्रहरी। सभी से यह आह्वान करते हुए कॉमरेड असित भट्टाचार्य ने अपना वक्तव्य समाप्त किया।

शरतचन्द्र जयन्ती मनाई

घाटशिला में शरत जयंती समारोह में शामिल छात्र

घाटशिला (झारखण्ड) : ऑल इण्डिया डीएसओ की घाटशिला शाखा के तत्वावधान में एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई। इसमें एआईडीएसओ के राज्य सचिव कॉ. कन्हाई बारिक ने शरतचन्द्र के जीवन-संघर्ष व शरत साहित्य पर अपनी बात रखी। इसमें स्कूल-कॉलेज के 90 छात्र उपस्थित थे।

प्रतापगढ़ (उ.प्र.) : 17 सितम्बर को महान साहित्यकार शरतचन्द्र चट्टोपाध्याय की जयंती प्रतापगढ़ जिले के गजयिा क्षेत्र में एसयूसीआई(सी) के किशोर-किशोरियों के संगठन कॉमसोमोल की तरफ से मनायी गयी। इसकी अध्यक्षता कॉ. रामसमझ मौर्य ने की व संचालन कॉ. मिथिलेश कुमार मौर्य ने किया। कार्यक्रम की शुरूआत शरतचन्द्र की फोटो पर माल्यार्पण करके की गई। उसके बाद किशोर छात्र-छात्राओं ने क्रान्तिकारी व प्रगतिशील गीत प्रस्तुत किए। जयन्ती कार्यक्रम में एसयूसीआई(सी), उ.प्र. राज्य कमेटी सदस्य कॉ. पुष्पेन्द्र विश्वकर्मा, कॉ. राम आसरे मौर्य, का. अरुण प्रजापति ने शरत साहित्य पर प्रकाश डाला और आज के परिवेश में उनकी उपयोगिता पर ध्यानाकर्षण किया।

फ्री कोचिंग क्लास का शुभारम्भ

आरोन (म.प्र.) : एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) की आरोन इकाई द्वारा स्थानीय भगत सिंह बस्ती में बच्चों को पढ़ाने के मकसद से एक फ्री कोचिंग क्लास का शुभारम्भ किया गया। इसका नाम महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद के नाम पर रखा गया। इसके शुभारम्भ के लिए नगर के सम्माननीय शिक्षक श्री मनोहर भदोरिया, श्री सुरेन्द्र , श्री हरिओम कुशवाहा, श्री राजमल, डा. चन्द्रेश व पार्टी के स्थानीय प्रभारी मनीष श्रीवास्तव उपस्थित रहे। नगर में इस तरह की यह दूसरी क्लास है। कक्षा प्रति रविवार को दो घण्टे चलाई जाएगीजिसमें बच्चों को नैतिक शिक्षा और और विज्ञान पढ़ाने के साथ-साथ खेल-कूद, सांस्कृतिक गतिविधियां भी कराई जाएंगी।

मध्याह्न भोजन कर्मियों का...

(पृष्ठ 1 का शेष)

आर. ब्लॉक पर पहुंचने के बाद जुलूस सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए बिहार राज्य मध्याह्न भोजन कर्मी संघ के अध्यक्ष तथा केन्द्रीय मजदूर संगठन एआईयूटीयूसी के राज्य सचिव प्रमोद कुमार ने कहा कि केन्द्र व राज्य की सरकार चाहे विकास और तरक्की की जितनी भी बात क्यों न करे, दरअसल दोनों सरकार अमीरपक्षीय आम जनता विरोधी नीतियों को लेकर ही चल रही हैं। बिहार में दलित मुख्यमंत्री के होते हुए भी दलितों-गरीबों के पक्ष में नीतियां तय नहीं हो रही हैं। असंगठित क्षेत्र के अकुशल मजदूरों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी 188 रुपये प्रति दिन है, जबकि मध्याह्न भोजन कर्मियों को 1000 रुपये प्रति माह मजदूरी मिलती है, जो मात्र लगभग 33 रुपये प्रति दिन होता है। उन्होंने मध्याह्न भोजन कर्मियों को आगाह करते हुए कहा कि वैसे संगठन जो सरकार के साथ सांठ-गांठ कर चलते हैं और मध्याह्न भोजन कर्मियों को लेकर आंदोलन की बात भी करते हैं, वे आंदोलन को सही मुकाम तक नहीं पहुंचा सकते। श्री कुमार ने अपने हक-अधिकार के लिए मध्याह्न भोजन कर्मियों को ताकतवर आंदोलन निर्मित करने की अपील की।

सभा को बिहार राज्य मध्याह्न भोजन कर्मी संघ के महासचिव पुनीत राय, धर्मेन्द्र कुमार, राम नरेश राम, सरिता देवी, चमरू सदा, महेन्द्र महतो, चन्द्रदेव महतो, अर्जुन पासवान, रघुनाथ महतो, शत्रुघ्न साह, रवीन्द्र चौधरी, रंजीत कुमार, इन्दु देवी आदि ने भी संबांधित किया।

जनवादी, धर्मनिरपेक्ष व वैज्ञानिक शिक्षा दिवस के रूप में देश भर में मनाई गई ईश्वरचन्द्र विद्यासागर जयन्ती

ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक स्टूडेन्ट्स ऑर्गेनाइजेशन (एआईडीएसओ) की अखिल भारतीय कमेटी के आह्वान पर 26 सितम्बर को भारतीय नवजागरण काल के महान समाज सुधारक ईश्वरचन्द्र विद्यासागर की 194वीं जयंती पर राष्ट्रीय स्तर पर ''जनवादी, वैज्ञानिक व धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दिवस'' के रूप में मनाने का आह्वान किया गया।

पटना (बिहार) : ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमिटी के तत्वावधान में भारतीय नवजागरण के अग्रदूत, महान समाज सुधारक व शिक्षा शास्त्री ईश्वरचन्द्र विद्यासागर की 194वीं जयंती के अवसर पर 26 सितम्बर को स्थानीय आई एम ए हॉल में शिक्षा बचाओ कन्वेंशन का आयोजन किया गया।

कन्वेंशन का उद्घाटन करते हुए शिक्षाविद् व पटना विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक प्रो. विनय कुमार कंठ ने कहा कि भारतीय नवजागरण एवं आजादी आंदोलन के अग्रदूतों ने देश में मनुष्य-निर्माण व चरित्र-निर्माण के औजार के तौर पर धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक व जनवादी शिक्षा का सपना देखा था। लेकिन आज देश के नीति-निर्माताओं ने उन मनीषियों के अधूरे सपने को पूरा करने की बजाय शिक्षा को बिकाऊ वस्तु में तब्दील कर दिया है। विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर बोलते हुए प्रो. कंठ ने कहा कि कोर्स का संदर्भ, विषय वस्तु और शिक्षा पद्धतियों में ना तो सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और ना ही निर्देशित करना चाहिए। इसे लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए शिक्षाविदों की समितियों द्वारा निर्णित और लागू किया जाना चाहिए।

कन्वेंशन को संबोधित करते हुए एएन सिन्हा समाज अध्ययन शोध संस्थान के पूर्व निदेशक प्रो. एम. एन. कर्ण ने कहा कि शिक्षा को मौलिक अधिकार के दायरे में लाने के लम्बे-चौड़े दावे के बावजूद शिक्षा अधिकार कानून-2009 वास्तव में शिक्षा से वंचित गरीब परिवार के बच्चों के किसी भी अधिकार की गारंटी नहीं करता है। दरअसल सरकार अधिकार के नाम पर 6 से 14 साल तक के बच्चों के अलावा किसी भी तरह की शिक्षा देने की जिम्मेवारी को नकार रही है।

कन्वेंशन को संबोधित करते हुए मानवाधिकार संगठन पीयूसीएल की प्रांतीय अध्यक्ष व पटना विवि की इतिहास विभाग की प्राध्यापिका प्रो. डेजी नारायण ने कहा कि कोई छात्र पढ़ाई में कड़ी मेहनत करने के लिए मानसिक तौर पर तैयार नहीं हो सकता, यदि उसे इस बात की जानकारी हो कि अगली कक्षा में उसका जाना तय है। परीक्षा होने की वजह से आज भी छात्रों में पढ़ाई के प्रति जो थोड़ी-बहुत रूचि बरकरार है, वह पास-फेल प्रथा के न रहने से खत्म हो जायेगी।

पटना विवि के इतिहास विभाग की प्राध्यापिका प्रो. भारती एस कुमार ने कहा कि प्राथमिक स्कूलों की दयनीय हालत के चलते ही क्षमता से भी आगे बढ़कर अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने की उम्मीद में निम्न मध्यम वर्ग के करोड़ों अभिभावक महंगे निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर हो गये हैं। फलस्वरूप शिक्षा का व्यवसाय बुनियादी स्तर से ही फल-फूल रहा है।

चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता अक्षय कुमार ने द चिल्ड्रेन राइट्स एण्ड यू 2013 के सर्वे रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 1, 48, 696 स्कूलों का भवन नहीं है। 1 लाख 65,742 स्कूलों में पेय जल की सुविधा नहीं है। 4,55, 561 स्कूलों में शौचालय नहीं है। 1,14,531 स्कूल मात्र एक-एक शिक्षक के भरोसे संचालित किए जा रहे हैं। शिक्षकों की कमी की भरपाई अंशकालिक शिक्षकों की बहाली कर किया जा रहा है। शिक्षा के सभी स्तर शिक्षकों की कमी की समस्या से जुझ रहे हैं। अनेक माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के विभाग, अधिकांश अंशकालिक शिक्षकों तथाकथित अतिथि शिक्षकों के सहारे चलाये जा रहे हैं। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि क्या पर्याप्त संख्या में योग्य और स्थायी शिक्षकों के बिना वास्तविक रूप में अच्छी शिक्षा संभव है?

अपने संबोधन में बीआईटी, पटना के प्राध्यापक प्रो. आशीष रंजन ने कहा कि सरकार को पुलिस-मिलिट्री बजट तथा नौकरशाहों पर होने वाले खर्च में कटौती कर शिक्षा के लिए कोष मुहैया कराना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय अनुदानप्राप्त संस्थाओं के अनुदान में कटौती करता जा रहा है। कन्वेंशन को संबोधित करते हुए प्रख्यात गणित शिक्षक विकास राही ने कहा कि गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के छात्रों की पहुंच से उच्च शिक्षा बाहर हो गयी है। साथ ही बाजारोन्मुखी पाठ्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, इतिहास, साहित्य जैसे सामान्य विषयों के पाठ्यक्रमों को हतोत्साहित किया जा रहा है।

अपने संबोधन में साहित्य आलोचक व पटना विवि के हिन्दी के प्राध्यापक प्रो. तरूण कुमार ने कहा कि केन्द्र सरकार शिक्षा क्षेत्र में निजी एवं विदेशी पूंजी निवेश को सुगम बनाने के लिए यूजीसी, एनसीइआरटी जैसी एजेंसियों के माध्यम से परीक्षा और उसके मूल्यांकन की पूरी प्रक्रियाओं में उलट-फेर कर जनवादी मूल्यों पर कुठाराघात कर रही है। उन्होंने इस बात की आशंका व्यक्त की कि आंतरिक मूल्यांकन पर जोर होने से शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार में वृद्धि होगी।

कन्वेंशन की अध्यक्षता करते हुए एनआईटी, पटना के से. नि. प्राध्यापक प्रो. संतोष कुमार ने कहा कि केन्द्र मे बीजेपी के नेतृत्व में गठित सरकार की नयी एचआरडी मंत्री समाज में गिरते मूल्यों पर विलाप कर शिक्षा के 'भारतीयकरण' की वकालत तो कर रही हैं, पर वे शिक्षा क्षेत्र में निजीकरण-व्यापारीकरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही हैं। प्रो. कर्ण ने शिक्षा पर हो रहे घातक हमलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने और सही मायने में धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक व जनवादी शिक्षा की मांग पर ताकतवर शिक्षा आंदोलन निर्मित करने की अपील की।

इनके अलावा पीयूसीएल के पूर्व राज्याध्यक्ष फादर फिलिप मंथरा, शिक्षा शास्त्री और सेवानिवृत्त शिक्षक आर. एन. झा., मुजफ्फरपुर से लालबाबू राय, दरभंगा से लाल कुमार, मुंगेर से रमण सिंह, भागलपुर से रौशन कुमार रवि, जहानाबाद से राजू कुमार, अरवल से दीपक कुमार आदि ने भी कन्वेंशन को संबोधित किया। सूर्यकर जितेन्द्र ने कन्वेंशन का मूल प्रस्ताव पेश किया। मंच संचालन इन्द्रदेव राय ने किया। धन्यवाद ज्ञापन ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमिटी, बिहार चैप्टर की सचिव साधना मिश्रा ने किया।

जौनपुर

दिल्ली : आठवीं कक्षा तक बेरोकटोक पास करने तथा सरकारी स्कूलों के गिरते स्तर के खिलाफ 14 सितम्बर को त्रिनगर में शिक्षा बचाओ कमेटी की ओर से सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर जी. सिंह ने वक्तव्य रखा तथा सभा का संचालन त्रिनगर इकाई के संयोजक सुरेश तुफान ने किया।

जौनपुर (उ.प्र.) : एआईडीएसओ की जौनपुर जिला कमेटी द्वारा 26 सितम्बर के दिन जिलाधिकारी जौनपुर के कार्यालय के समक्ष छात्र प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ। जुलूस में शामिल विभिन्न स्कूल-कॉलेजों के छात्र-छात्राएं अपने हाथों में मांग पट्टिकाएं, बैनर व झण्डे लिये हुए जोरदार नारे लगाते हुए पालीटेक्नीक, ओलन्दगंज, कचहरी रोड होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और धरने पर बैठ गये। धरने पर बैठे छात्रों को सम्बोधित करते हुए संगठन के उ.प्र. राज्य सचिव कॉ. हरिशंकर मौर्य ने कहा कि शिक्षा को आज व्यापारिक वस्तु में तब्दील कर दिया गया है, शिक्षा महंगी होती जा रही है जिससे अनगिनत छात्र उच्च शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं। पाठ्य क्रमों में मनमाना परिवर्तन कर मानव निर्माण व चरित्र निर्माण व सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना पैदा करने वाली शिक्षा को नष्ट किया जा रहा है। दूसरी तरफ प्रचार माध्यमों से अश्लीलता, नग्नता, नशाखोरी, हिंसा का धड़ल्ले से प्रचार किया जा रहा है। लाखों पोर्न वेबसाइटों, टीवी चैनलों द्वारा छात्र-नौजवानों की सांस्कृतिक-नैतिक रीढ़ को तोड़ा जा रहा है ताकि वे किसी अन्याय-अत्याचार का डट कर मुकाबला करने के लिए उठ खड़े न हो सकें। यह सब एक साजिश के तहत प्रायोजित है। उन्होंने सरकार की शिक्षा-विरोधी नीतियों के खिलाफ छात्र आन्दोलन तेज करने की जरूरत पर बल दिया।

सभा की अध्यक्षता संगठन के जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार ने की और संचालन विकास कुमार ने किया। संगठन की ओर से 9 सूत्रीय मांगपत्र जिलाधिकारी जौनपुर को सौंपा गया।

भोपाल (म.प्र.) : ऑल इण्डिया सेव एजुकेशन कमेटी की मध्य प्रदेश राज्य इकाई के तत्वावधान में देश-प्रदेश की ज्वलंत शैक्षणिक समस्याओं को लेकर जी.टी.बी. कॉम्पलेक्स के तृतीय तल सभाकक्ष में एक नागरिक परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा में मुख्यवक्ता ऑल इंडिण्या सेव एजुकेशन कमेटी के राष्ट्रीय सचिव मण्डल सदस्य, शिक्षा बचाओ आन्दोलन के लिए संघर्षरत सौरभ मुखर्जी ने कहा कि आर.टी.ई. एक्ट 2009 को देश में कक्षा-8 तक बेरोकटोक पास करने की नीति ने शिक्षा की रीढ़ को ही तोड़ दिया है, वास्तव में सरकार औद्योगिक घरानों के पक्ष में अनपढ़ नौजवान मजदूरों की फौज खड़ा करना चाहती है। इसके अलावा महाविद्यालयों में सेमेस्टर प्रणाली ने कॉलेजों को परीक्षा केन्द्र के रूप में तब्दील कर दिया हैं, जिसने शिक्षा के निजीकरण-व्यवसायीकरण की प्रक्रिया को और तेज कर दिया है, तीन वर्ष की डिग्री कोर्स में चार से पॉच वर्ष तक का समय लग रहा है। बेतहासा फीस वृद्धि ने गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को कॉलेज की पढ़ाई को सपने जैसा बना दिया है।

नागरिक परिचर्चा के आयोजक व ऑल इण्डिया सेव एजुकेशन कमेटी के मध्य प्रदेश राज्य संयोजक डॉ. रामअवतार शर्मा ने कहा कि केन्द्र की पिछली यू.पी.ए. सरकार की भांति भाजपा नेतृत्व में बनी नई सरकार भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एवं अन्य तौर तरीको से

(शेष पृष्ठ 6 पर)

भोपाल

ईश्वरचन्द्र विद्यासागर जयन्ती ...

(पृष्ठ 5 का शेष)

शिक्षा के निजीकरण-व्यापारीकरण की प्रक्रिया को और तेज कर दिया हैं जिससे मनुष्य निर्माण और चरित्र निर्माण की प्रक्रिया बाधित हो रही है। शिक्षा के साम्प्रदायीकरण के साथ-साथ शिक्षा के भारतीयकरण के नाम पर हिन्दू धर्मान्धता को विभिन्न पाठ्यक्रमों में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। जैसे, म.प्र. सरकार दो अक्टूबर से गर्भ संस्कार पाठ्यक्रम शुरू करने वाली है जिसमें गर्भवती महिलाओं को तपोवन केन्द्रों में हिन्दू ऋषि-मुनियों के किस्से-कहानी सुनाये जायेंगे जबकि इस तरह के पाठ्यक्रमों का आधुनिक युग में शिक्षा के वैज्ञानिक तौर तरीके से कोई वास्ता नहीं है। इसके अलावा रोजगारोन्मुखी शिक्षा के नाम पर ब्यूटी साइंस, फेशन डिजाइनिंग, होटल मेनेजमेन्ट जैसे डिग्री-डिप्लोमा कोर्सो को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने की कोशिश की जा रही है। भाषा दर्शन, साहित्य, भौतिकी जैसे पाठ्यक्रमों को आज अनुत्पादक बताया जा रहा है। भोपाल के प्रसिद्ध ट्रेड यूनियन नेता, साहित्यकार व शिक्षा प्रेमी श्री जी.एस. आशीवाल ने कहा कि ईश्वरचन्द्र विद्यासागर और भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद का सपना आज भी पूरा नहीं हुआ है। आज हिन्दूस्तान में 35 करोड़ लोगों को 2 टाइम का खाना नहीं मिलता। उनके 7 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और 90 प्रतिशत बच्चे 12 वीं से आगे नहीं पढ़ पाते। ऐसी स्थिति में शिक्षा को बचाने के लिए कर्मचारियों, शिक्षकों, अभिभावाकों आदि सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। सभी को आगे आना चाहिए।

नगर के सुप्रसिद्ध वरिष्ठ पत्रकार व सामाजिक और शिक्षा आन्दोलन में सक्रिय श्री एल.एस. हरदेनिया ने कहा कि शिक्षा सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं है। उसे रोजगार का साधन नहीं समझना चाहिए हमारे देश को अशिक्षित रखने में शासन का निहित स्वार्थ ज्यादा है। शिक्षा क्षेत्र में जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए।

जाने-माने साहित्यकार व पूर्व प्रशासनिक अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह ने कहा कि शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकता को आज शासन की नीतियों के चलते गरीबों से दूर रखा जा रहा है। वर्तमान में शिक्षा पर सांप्रदायीकरण का खतरा सबसे ज्यादा है। जैसे म.प्र. में गीता के कुछ अंशों को लाया जाना शिक्षा में साम्प्रदायीकरण का उदाहरण है। परिचर्चा का संचालन करते हुये कमेटी के सदस्य अवनीश श्रीवास्तव ने भारतीय पुनर्जागरण के मनीषियों एवं आजादी आन्दोलन में गैर समझोतावादी धारा के महापुरुषों के जीवन-संघर्ष को याद करते हुये इस आंदोलन को तेज करने की अपील की।

अश्लील पोस्टरों के खिलाफ डीवाईओ ने सौंपा ज्ञापन

अशोकनगर (म.प्र.) : अश्लीलता, अपसंस्कृति, नशाखोरी के खिलाफ क्रांतिकारी युवा संगठन डीवाईओ द्वारा लगातार आंदोलन संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में एक धरना-प्रदर्शन कर कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया था और शहर में चौक-चौराहों पर से अश्लील पोस्टरों को हटाया जाने और अश्लील फिल्मों का प्रसारण रोके जाने की मांग की गई थी लेकिन जब जिला प्रशासन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई तो 28 सितम्बर को युवा संगठन द्वारा शहर के सभी चौराहों पर लगे अश्लील फिल्मी पोस्टरों पर कालिख पोती गई। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क पर एकत्रित होकर 'इंकलाब जिंदाबाद', 'शहीद भगत सिह के देश में अश्लीलता परोसना बंद करो', 'सेन्सर बोर्ड होश में आओ', 'महिलाओं पर बढ़ते अपराधों पर रोक लगाओ', 'डीवाईओ जिंदाबाद' के नारों के साथ शहर के प्रमुख चौराहों से गुजरते हुए कलेक्टरेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि तत्काल शहर में लगे गन्दे पोस्टरों को हटाया जाए व अश्लील फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक लगाई जाए। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने अन्यथा आगामी समय में संगठन द्वारा और तीव्र आंदोलन किये जाने की चेतावनी दी।

बिजली की दुर्व्यवस्था के खिलाफ धरना-प्रदर्शन

बदलापुर, जौनपुर (उ.प्र.) : अंधाधुंध बिजली कटौती से त्राही-त्राही कर रही जनता और दुकानदारों पर दर्ज मुकदमें वापस लेने की मांग को लेकर ऑल इण्डिया डी.वाई.ओ. ने जुलूस निकाल कर बदलापुर तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। क्षेत्र के ग्रामीणों, किसानों, वकीलों व किसान एकता मंच ने आन्दोलन का समर्थन किया। संगठन की ओर से सात सूत्रीय मांगों से सम्बन्धित एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी की मार्फत मुख्यमंत्री को भेजा गया गया।

संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता पहले पुराने बाजार के बाग में इकट्ठे हुए और वहां से जुलूस निकाल कर तहसील परिसर पहुंचे। आक्रोशित लोगों ने विद्युत विभाग के गलत कदमों के खिलाफ जम कर नारे लगाये। दुकानदारों पर दर्ज मुकदमें वापस लेने, बिजली कटौती रोकने, नहरों में टेल तक पानी देने की मांग की। धरना सभा को एआईडीवाईओ के राज्य सचिव कॉ. रविशंकर मौर्य, किसान एकता मंच की तरफ से कृष्ण सिंह, व्यापार मंडल की तरफ से अनिल सिंह शांति, एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के जिला कमेटी सदस्य कॉ. दिनेशकांत दुबे, अधिवक्ता संघ की तरफ से अवीन्द्र प्रताप सिंह, विष्णु दत्त शुक्ल आदि ने सम्बोधित किया। सभा की अध्यक्षता कॉ. इन्दु कुमार शुक्ल ने की और संचालन कॉ. प्रमोद कुमार शुक्ल ने किया।

भुवनेश्वर व दुर्ग में विशाल छात्र रैली

भुवनेश्वर (ओडिशा) : ज्वलंत शैक्षणिक समस्याओं के खिलाफ सचिवालय पर ऑल इण्डिया डीएसओ की ओर से 12 सितम्बर को विशाल छात्र प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय विरोध दिवस के अवसर पर आयोजित इस प्रदर्शन में पूरे राज्य भर से आये सैकड़ों छात्रों ने भाग लिया। एआईडीएसओ के राज्याध्यक्ष कॉ. अक्षय दास, उपाध्यक्ष सुभाष नायक व गणेश त्रिपाठी, सचिव सुभाषीश पहराज, सचिव मण्डल सदस्य केदारनाथ साहू, सिद्धार्थ रथ, सोमनाथ बेहरा, बाबी बालाबंटारे, कृष्णारानी साहू, कार्तिक मोहंता, प्रमानंद साहू, खगेश्वर मोहंता, जयंता मोहंती, नसीम सरकार, सुनील भोई, मधुस्मिता साहू, सुरजीत स्वैन और प्रकाश दास आदि ने सभा को सम्बोधित किया।

एआईडीएसओ ने बाढ़ पीड़ित छात्रों की तमाम तरह की फीस माफ करने, फीस बढ़ोतरी वापस लेने, 165 स्कूलों को बंद करने का फैसला वापस लेने, 8वीं कक्षा तक पास-फेल प्रणाली दोबारा चालू करने, स्कूल-कॉलेजों में खाली पड़े तमाम पद भरने के लिए शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति करने, विभिन्न तरह के शिक्षण संस्थानों में फीस ढांचे में एकरूपता लाने, बीपीयूटी द्वारा समय पर परीक्षाओं का संचालन करने, शिक्षा का निजीकरण-व्यापारीकरण बंद करने, एसएसए, आरएमएसए और आरयूएसए को रद्द करने, छात्राओं पर यौन हमलों की रोकथाम करने, सभी स्कूलों में आर्ट, संगीत और पीइटी के शिक्षक नियुक्त करने, सभी तहसीलों में आसान तरीके से विभिन्न तरह के सर्टिफिकेट छात्रों को मुफ्त मुहैया कराने, शैक्षणिक सत्र के दौरान छात्रों को स्टाइफण्ड समय पर देने, ब्लॉक ग्रांट सिस्टम खत्म करने और सभी संस्थानों को पूरी आर्थिक सहायता प्रदान करने, सेमेस्टर, ट्राइमेस्टर और कोर्स क्रेडिट सिस्टम रद्द करने की मांग की।

दुर्ग (छ.ग.) : ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेन्ट्स ऑर्गेनाइजेशन (ए.आई.डी.एस.ओ.) छ.ग. राज्य संगठन समिति के तत्वावधान में 20 सितम्बर को प्रतिरोध दिवस के अवसर पर शिक्षा की विभिन्न समस्याओं के खिलाफ दुर्ग में प्रदर्शन किया गया। यह विरोध प्रदर्शन साइन्स कॉलेज दुर्ग से शुरू हुआ और मालवीय नगर, पालीटेक्नीक कॉलेज, बस स्टैण्ड, मल्टीपरपज हायर सेकेण्डरी स्कूल से होकर कचहरी चौक होते हुए सभा में परिवर्तित हो गया। सभा को सम्बोधित करते हुए ए.आई.डी.एस.ओ. के छ.ग. राज्य संयोजक कॉ. आत्मा राम साहू ने कहा कि आज हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था अत्यंत दुखभरी तस्वीर पेश कर रही है। आज शिक्षा क्षेत्र में केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा लगातार तीव्र हमला किया जा रहा है और आम मेहनतकश, गरीब, मध्यम वर्ग के छात्रों को शिक्षा नहीं देने की साजिश की जा रही है। तीव्र गति से शिक्षा का निजीकरण-व्यापारीकरण कर चंद मुठ्ठीभर उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को अधिक से अधिक मुनाफा कमाने दिया जा रहा है। हर वर्ष शिक्षा क्षेत्र में बेतहाशा फीस वृद्धि ने छात्रों की कमर तोड़कर रख दी है। शिक्षा को गैट्स क्षेत्र में लाकर इसे खरीद-फरोक्त की वस्तु में तब्दील कर दिया जा रहा है। कक्षा पाँचवी व आठवीं की बोर्ड परीक्षा व पास-फेल प्रणाली समाप्त कर शिक्षा की नींव को ही बर्बाद कर दिया गया है। ग्रेडिंग सिस्टम, सेमेस्टर प्रणाली, आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली आदि शिक्षा-विरोधी नीतियां लागू कर शिक्षा की गुणवत्ता व ज्ञान को ही खत्म कर दिया जा रहा है। जबकि आजादी आंदोलन के क्रांतिकारियों व मनीषियों ने सभी के लिए अनिवार्य, जनवादी और मुफ्त शिक्षा की मांग की थी क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य उन्नत चरित्र व मनुष्य निर्माण करना है जिसके बिना सभ्य समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

उन्होंने आम लोगों, शिक्षा प्रेमियों और छात्र समुदाय से शिक्षा को बचाने के लिए जोरदार छात्र आंदोलन संगठित करने का आह्वान किया। इस विरोध प्रदर्शन में विभिन्न स्कूल-कॉलेजों के लगभग 70 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया।

दुर्ग

रांची

सेमेस्टर प्रणाली हटाने, फीस बढ़ोतरी रोकने एवं फेल-पास प्रणाली चालू करने की मांग को लेकर

छात्रों का राज्य स्तरीय प्रदर्शन

भोपाल (म.प्र.) : सेमेस्टर प्रणाली वापस लेने, फीस बढ़ोतरी रोकने एवं कक्षा 8वीं तक भी फेल-पास प्रणाली चालू करने की मांग को लेकर 12 सितम्बर को डीएसओ के बैनर तले राज्य के विभिन्न जिलों से आये छात्रों ने राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन किया। डीएसओ के अखिल भारतीय सचिव मण्डल सदस्य कॉ. सचिन जैन ने कहा कि छात्रों के लगातार विरोध के चलते ही शासन द्वारा सेमेस्टर प्रणाली पर मतदान का निर्णय लिया गया है।

सरकार साधारण कोर्स हटा कर कोर्स क्रेडिट सिस्टम लागू करने जा रही है। इससे छात्रों की सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी। गुना से संगठन के कॉ. योगेश धाकड़ ने कहा कि सरकार की शिक्षा-विरोधी नीतियों से शिक्षा संकुचित और शिक्षा की नींव कमजोर होती जा रही है। शासन द्वारा 8वीं तक पास-फेल सिस्टम खत्म किये जाने के दुष्परिणाम स्वरूप ही इस बार 9वीं कक्षा का परिणाम 26 प्रतिशत रहा है। खुद मानव संसाधन मंत्रालय की स्थाई समिति की रिपोर्ट में कई नकारात्मक पहलू सामने आये है। जैसे कक्षा 3 के 61.3 प्रतिशत बच्चे कक्षा 1 की किताब नहीं पढ़ पाते हैं। कक्षा 5वीं के 46.5 प्रतिशत बच्चे 2 अंकों के सरल सवाल भी नहीं कर पाते हैं। डीएसओ के भोपाल जिला सचिव विनोद लोगरिया, अनुराधा पटेल, सागर, श्रुति और नित्या ग्वालियर ने भी अपनी बात रखी।

भोपाल में छात्र रैली को सम्बोधित करते हुए सचिन जैन

कार्यक्रम का संचालन डीएसओ के अखिल भारतीय सचिव मण्डल सदस्य मुदित भटनागर ने किया। उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन पढ़ा गया जिसका वाचन कु. निवेदिता ने किया।

राँची विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय के समक्ष छात्र प्रदर्शन

राँची (झारखण्ड): राँची विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों से एवं ऑटोनोमस कॉलेजों से पास किए हुए छात्र व छात्राओं के पी.पी.जी. में नामांकन प्रक्रिया में समानता, विश्वविद्यालय के सभी विभागों में सीटों की कमी एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं के अभाव के खिलाफ 22 सितम्बर को एआईडीएसओ राँची जिला कमिटी के तत्वावधान में राँची विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय के समक्ष एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया। यह प्रदर्शन एक जुलूस के रूप में राँची के जयपाल सिंह स्टेडियम से शुरू होकर कुलपति कार्यालय तक गया और वहाँ पहुँचकर लगभग 1 घण्टे तक कुलपति के कार्यालय का घेराव किया गया। जुलूस एक सभा के रूप में तब्दील हो गया।

एआईडीएसओ के राँची जिला सचिव वन्हिशिखा समाजपति ने कहा कि आज राँची विश्वविद्यालय सहित पूरे देश भर में शिक्षा की स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो गई है। प्रथम वर्ग से लेकर पी.जी. स्तर तक की शिक्षा में धीरे-धीरे गुणवत्ता नष्ट की जा रही है। एक ओर तो राँची विश्वविद्यालय के सभी विभागों में सीटों की अत्यन्त ही कमी है, वहीं दूसरी ओर राँची विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों की तुलना में ऑटोनोमस कॉलेजों की नामांकन प्रक्रिया, सिलेबस और परीक्षा की प्रक्रिया से लेकर परीक्षा के मूल्यांकन की प्रक्रिया में भी बहुत बड़ी असमानता है। ऑटोनोमस कॉलेजों में होने वाली कई छोटी-छोटी परीक्षाओं में खुद उसी कॉलेज के शिक्षक अपने हाथों से मूल्यांकन कर अंक प्रदान करते हैं और ऐसे कई अन्य कारणों से ऑटोनोमस कॉलेजों के छात्र अंगीभूत कॉलेजों के छात्रों की तुलना में ज्यादा अंक प्राप्त करते हैं। फलस्वरूप पी.जी. में नामांकन के दौरान ऑटोनोमस कालेजों के छात्रों द्वारा किए गए आवेदन को तरजीह दी जाती है और यहाँ अंगीभूत कॉलेजों के कई छात्र नामांकन से वंचित रह जाते हैं। हम किसी भी बिन्दु पर ऑटोनोमस कॉलेजों के छात्रों के खिलाफ नहीं हैं बल्कि हम खिलाफ हैं सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन की इन बेबुनियादी और शिक्षाविरोधी नीतियों के, जिनके कारण हजारों छात्रों का भविष्य दाँव पर लगा हुआ है। सरकार अगर चाहे तो जहाँ पहले से स्थापित कॉलेजों के सौन्दर्यकरण पर करोड़ों रुपये खर्च कर उसे ऑटोनोमस कालेज बना रही है और उसे विश्वविद्यालय के नियंत्रण से बाहर कर रही है, वहीं सरकार आटोनोमस कॉलेजों के छात्रों के लिए उसी कॉलेज में पी.जी. की पढ़ाई की भी व्यवस्था कर सकती है। इसके अलावा हम यह भी जानते हैं कि विश्वविद्यालय के सभी विभागों में शिक्षकों की कमी, पुस्तकालय व प्रयोगशालाओं का अभाव, शौचालय में गंदगी जैसी अनेक समस्याएं हैं। हम विश्वविद्यालय प्रशासन व सरकार से मांग करते हैं कि उपर्युक्त बिन्दुओं को गम्भीरता से लेते हुए उचित व्यवस्था व नियम लागू किए जाएँ और राँची विश्वविद्यालय के सभी विभागों में नामांकन हेतु आवेदन की बहुलता को देखते हुए अविलम्ब सीटें बढ़ाई जाएं।

कार्यक्रम के अंत में एआईडीएसओ राँची जिला अध्यक्ष विवेक कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल जिसमें वन्हिशिखा समाजपति, अभिषेक कुमार, अंजलि कुमारी और संतोष कुमार उपस्थित थे, विश्वविद्यालय के कुलपति से मिला और ज्ञापन सौंपा।

सुल्तानपुर (उ.प्र.) में परिचर्चा

5 सितम्बर को तिकोनिया पार्क में एआईडीएसओ सुल्तानपुर शहर इकाई की तरफ से 'शिक्षक दिवस' के अवसर पर शिक्षा की समस्याओं के लेकर एक चर्चा-परिचर्चा की गयी। इसका संचालन एआईडीएसओ राज्य कमेटी सदस्य कॉ. राम आशीष मौर्य ने किया। मुख्य वक्ता राज्य सचिव कॉ. हरिशंकर मौर्य ने कहा कि आज सरकार की नीतियों के द्वारा शिक्षा पर चौतरफा हमला किया जा रहा है जिसके खिलाफ एक व्यापक और जुझारू छात्र आन्दोलन खड़ा करने की जरूरत है।

मुख्य अतिथि-प्रियांशुल शुक्ल और संजय शुक्ल थे। परिचर्चा की अध्यक्षता एआईडीएसओ के शहर इंचार्ज दिवाकर पाण्डेय ने की। परिचर्चा में कॉ. मिथिलेश मौर्य, सतीशचन्द्र यदुवंशी, राम अछैवर यादव, आशीष उपाध्याय और अमित सिंह आदि ने भाग लिया।

विक्रम विवि, उज्जैन के वीसी से मिले डीएसओ नेता

इन्दौर (म.प्र.) : विक्रम युनिवर्सिटी, उज्जैन के वाइस चांसलर श्री जे एल कौल से एआईडीएसओ का एक प्रतिनिधिमण्डल मिला और हाल ही में बजरंग दल, विश्व हिन्दू परिषद और एबीवीपी द्वारा उन पर किये हमले के विरोध में उन्हें एकजुटता और समर्थन का एक पत्र दिया। प्रतिनिधि मण्डल में मुदित भटनागर, सचिन जैन, प्रमोद नामदेव और मितिन अग्रवाल शामिल थे।

कॉमरेड रणसिंह लाल सलाम

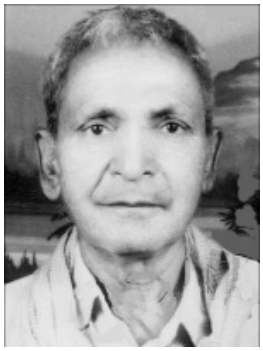

सोनीपत (हरियाणा) : कॉ. रणसिंह ने 8 सितम्बर को अपने पैतृक गाँव माहरा जिला सोनीपत में अन्तिम सांस ली। वे 95 वर्ष के थे। कॉमरेड रणसिंह 1986 के आस-पास कॉ. हरिप्रकाश के सम्पर्क में आए थे और सर्वहारा के महान नेता कॉ. शिवदास घोष के चिंतन से प्रभावित होकर उन्होंने अपने को सर्वहारा वर्ग की राजनीति के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया था। उन्होंने एसयूसीआई (सी) की सदस्यता हासिल की और ऑल इण्डिया कृषक खेतमजदूर संगठन विकसित करने की जिम्मेदारी संभाली। वे पेशे से एक अच्छे अध्यापक थे। क्षेत्र के लोग गहरे दुख और अपार सम्मान व श्रद्धा के साथ उन्हें याद करते हैं। उनके निधन से पार्टी व आन्दोलन की अपूर्णीय क्षति हुई है।

25 सितम्बर को माहरा गाँव में कॉ. रणसिंह की याद मे एक शोक-सभा आयोजित की गई। इसमें क्षेत्र के तमाम नागरिकों ने भाग लिया। सभा को एसयूसीआई(सी) हरियाणा राज्य सांगठनिक कमेटी सदस्यगण कॉ. हरिप्रकाश व कॉ. ईश्वर सिंह राठी (जिला सचिव) ने सम्बोधित किया। कॉ. रणसिंह के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किये।

कॉमरेड रणसिंह लाल सलाम!

कॉमरेड फूलचंद शर्मा लाल सलाम

भिवानी (हरियाणा) : कॉ. फूलचन्द शर्मा ने 21 सितम्बर को अपने पैतृक गाँव ढाणी माहू जिला भिवानी में अन्तिम सांस ली। वे 85 वर्ष के थे। वे लम्बे अर्से से बीमार चल रहे थे। सर्वहारा के महान नेता कॉ. शिवदास घोष के चिंतन से प्रभावित होकर वे 1976 के आस-पास एसयूसीआई(सी)से जुड़े थे। उन्होंने पार्टी की सदस्यता हासिल की और लोकल कमेटी सदस्य बने। उन्होंने ऑल इण्डिया कृषक खेतमजदूर संगठन में काम किया। वे आजीवन सर्वहारा वर्ग की राजनीति करते रहे। एसयूसीआई(सी) हरियाणा राज्य सांगठनिक कमेटी सदस्य व भिवानी जिला सचिव कॉ. रामफल, जिला कमेटी सदस्य कॉ. जिले सिंह, रोहताश, धर्मबीर के अलावा स्थानीय कॉमरेड उम्मेद सिंह, सुखबीर व आसपास के गाँवों के कॉमरेडों ने उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धासुमन अर्पित किये और उनकी अन्तिम यात्रा में शामिल शामिल हुए। लाल सलाम देते हुए सभी ने अपने दिवंगत साथी को अलविदा कहा। उनके निधन से क्षेत्र के लोग दुखी हैं और पार्टी व जनआन्दोलन की अपूर्णीय क्षति हुई है।

2 अक्तूबर को उनकी याद मे एक शोक-सभा आयोजित हुई। इसमें क्षेत्र के अनेक नागरिकों ने भाग लिया।

कॉमरेड फूलचन्द शर्मा लाल सलाम!

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2012-2014
Posting at IPMBC on 7–8 and 22–23 Fortnightly, Date of Printing :5 Oct, 2014

महिलाओं व बच्चियों पर बढ़ते अपराध, नशाखोरी, अश्लीलता, अपसंस्कृति के खिलाफ
महिलाओं का जिला सम्मेलन सम्पन्न

ग्वालियर(म.प्र.) : महिलाओं व बच्चियों पर बढ़ते अपराध, नशाखोरी, अश्लीलता, अपसंस्कृति के खिलाफ एआईएमएसएस की ग्वालियर इकाई का जिला सम्मेलन 24 अगस्त को सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरूआत में संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती छाया मुखर्जी द्वारा ध्वजारोहण और संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती छाया मुखर्जी, राष्ट्रीय महासचिव डॉ. एच.जी.जयलक्ष्मी, मध्यप्रदेश संयोजिका रचना अग्रवाल, ग्वालियर जिला अध्यक्ष आभा भूवरकर द्वारा शहीद वेदी पर पुष्पार्पण किया गया।

आभा भूवरकर की अध्यक्षता में हुए प्रतिनिधि अधिवेशन की शुरूआत गीत के साथ हुई। सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियों एवं महिलाओं की स्थिति पर प्रस्ताव सुचेता ने पेश किया। प्रतिनिधियों द्वारा चर्चा-बहस के बाद इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। संगठन की जिला सचिव श्रीमती प्रतिभा द्वारा सांगठनिक रिपोर्ट पेश की गई। इस अवसर पर डॉ.एच.जी.जयलक्ष्मी ने कहा कि महिलाओं पर बढ़ते हमले का एक बड़ा कारण अश्लील वेबसाइट व टी.वी. चैनल हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हें बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि कारगिल युद्ध एवं ईराक युद्ध के दौरान बहुत से चैनल और वेबसाइटें बंद कर दी गयी थीं। यदि सरकार चाहे तो इसे बंद कर सकती है पर उद्योगपतियों का अधिकतम मुनाफा हो इसलिए ऐसा नहीं करती। इस पर हमें आंदोलन के माध्यम से दबाव बनाना पड़ेगा।

प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए कॉ. छाया मुखर्जी ने महिलाओं को इस अन्याय-अत्याचार के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन तेज करने का आह्वान किया। सम्मेलन में जिलाध्यक्ष आभा भूवरकर तथा जिला सचिव सुचेता सक्सेना चुनी गईं।

शाम को खुले अधिवेशन की शुरूआत सांस्कृतिक गीतों से की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष आभा भूवरकर ने की। प्रतिनिधि सम्मेलन की कार्यवाही रिपोर्ट जिला सचिव सुचेता सेक्सना ने रखी। रचना अग्रवाल ने कहा कि महिलाओं व बच्चियों को अगर वास्तव में सुरक्षित समाज हमें देना है तो तमाम कारकों के खिलाफ आंदोलन चलाते हुए साथ ही साथ सांस्कृतिक आंदोलन भी चलाना होगा। श्रीमती छाया मुखर्जी ने कहा कि महिलाओं-बच्चियों एवं समाज की इस दुर्दशा का मुख्य कारण पूंजीवाद है। जब तक यह रहेगा समाज में दो वर्ग मौजूद रहेंगे। एक पूंजीपतियों का जो उत्पादन के साधनों पर अपना मालिकाना कायम करके बैठा है और दूसरा मजदूरों का जो अपनी मेहनत से हर चीज पैदा कर रहा है। महिलाएं दोहरे शोषण की शिकार हैं। एक तो इस पूंजीवाद शोषण की मार उन पर भी पड़ती है और दूसरे इसके द्वारा फैलायी जा रही सामंती सोच, पुरुषप्रधान सोच के कारण आज दमित-उत्पीड़ित हैं। इसे खत्म किये बगैर महिलाओं का भी समाज में इज्जत, सम्मान व बराबरी का अधिकार नहीं मिल पाएगा।

एसयूसीआई(सी) जिला सचिव सुनील गोपाल ने भी सभा को सम्बोधित किया। कार्यक्रम के अंत में सांस्कृतिक गतिविधियां हुई जिनमें कथक नृत्य एवं नाटक पेश किया गया।

जम्मू-कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के लिए
राहत सामग्री व कोष संग्रह

श्रीनगर के पास बडगांव में चल रहे चिकित्सा शिविर का दृश्य

मेडिकल सर्विस सेंटर एक सामाजिक स्वयंसेवी संगठन है जिसने पहले भी उत्तराखण्ड के केदारनाथ में बादल फटने से आई बाढ़ की आपदा के समय राहत कार्य किये और साल भर चिकित्सा शिविर चलाये, अब तमाम प्रतिकूलताओं के बावजूद मेडिकल सर्विस सेंटर जम्मू-कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटा हुआ है। 27 सितम्बर से जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर के पास बडगांव में चिकित्सा शिविर चला रहा है। बाढ़ पीड़ित अभी भी राहत कैम्पों में हैं। उनमें से बहुत लोगों को पता नहीं उनका पुनर्वास कब हो पायेगा। दूसरी तरफ यहां-वहां प्रशासन द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। दूषित पानी महामारी फैलने का कारण बन सकता है। फिर अभी सर्दियां आने वाली हैं जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ जाएंगी। उनकी मदद के लिए एसयूसीआई (सी) और मेडिकल सर्विस सेंटर की अपील के जवाब में उत्तराखण्ड के नागरिकों, शिक्षकों व डीएसओं की ओर से छात्रों ने 10 हजार रुपये के लगभग की दवाइयां और 21 हजार रुपये नकद राहत कोष श्रीनगर (उत्तराखण्ड) से संग्रह किया और श्रीनगर (जम्मु-कश्मीर) भेजने के लिए 1 अक्तूबर को दिल्ली में मेडिकल सर्विस सेंटर के सह सचिव डा. जितेन मुर्मु को सौंपा।

जम्मू-कश्मीर बाढ़ पीड़ितों के लिए मेडिकल राहत सामग्री संग्रह करके भेजने के बारे में यहां कलावती सरण बच्चों के हस्पताल में 26 सितम्बर को मीटिंग हुई। सीजीएचएस लाभार्थियों को कम दवाइयों की आपूर्ति और दवाइयों की कीमतों को रेगूलेट करने के लिए नेशनल फार्मास्यूटीकल अथोरिटी की शक्तियों में कटौती करने के रसायन व उर्वरक मंत्रालय के कदम के बारे में भी एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया क्योंकि इससे दवा निर्माता कम्पनियों को जीवन रक्षक दवाइयों सहित सभी दवाइयों की मनमानी कीमतें तय करने की छूट मिल जाएगी।

हरियाणा विधानसभा चुनाव में एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के उम्मीदवारों को विजयी बनायें

क्र.	वि.स. क्षेत्र	उम्मीदवार	चुनाव चिन्ह
1.	भिवानी	**कॉ.राजकुमार जांगड़ा**	
2.	तोशाम	**कॉ. रोहतास सैनी**	
3.	आदमपुर	**कॉ. हवा सिंह संघर्ष**	
4.	बहादुरगढ़	**कॉ. लालजी**	
5.	रोहतक	**कॉ.हरीशकुमार सैनी**	
6.	पुण्डरी	**कॉ.महाबीरसिंह कौल**	
7.	पेहवा	**कॉ.राजकुमार सारसा**	
8.	नारनौल	**कॉ.सुभाषचन्द हुडीना**	
9.	अटेली	**कॉ.बलबीरसिंह चन्दपुरा**	
10.	रेवाड़ी	**कॉ. बलराम यादव**	कांच का गिलास
11.	कोसली	**कॉ. रामकुमार**	
12.	सोनीपत	**कॉ. जयभगवान**	
13.	राई	**कॉ. देवेन्द्रसिंह दहिया**	
14.	गुड़गांव	**कॉ. श्रवण कुमार गुप्ता**	बैटरी टॉर्च

साम्प्रदायिकता-विरोधी दिवस के रूप में मनायी
शहीद-ए-आजम भगत सिंह जयंती

दिल्ली : ए.आई.डी.एस.ओ. दिल्ली-गाज़ियाबाद बॉर्डर लोकल कमेटी ने 28 सितम्बर शहीद-ए-आज़म भगत सिंह की 107वीं जयंती साम्प्रदायिकता-विरोधी दिवस के रूप में मनायी। फिरोजशाह कोटला जहाँ भगत सिंह और उनके साथियों ने मिलकर क्रान्तिकारी संगठन एच.एस.आर.ए. की स्थापना की थी, के ऐतिहासिक महत्व को समझते हुए कमेटी ने दिल्ली गेट से फिरोजशाह कोटला स्थित शहीद पार्क तक छात्र रैली निकाली जो सभा में तब्दील हो गई। शहीद भगत सिंह, राजगुरू व सुखदेव की मूर्तियों पर पुष्प अर्पित किये गये। सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव अशोक अरोड़ा, एआईडीएसओ के दिल्ली राज्याध्यक्ष कॉ. भास्करानन्द, एआईएमएसएस की दिल्ली राज्य सचिव कॉ. रितु कौशिक ने सभा को सम्बोधित किया। कार्यक्रम का संचालन कमेटी के अध्यक्ष कॉ. कुनाल पराशर ने किया। बाद में पार्क में वृक्षारोपण भी किया गया।

इस अवसर पर एआईडीएसओ द्वारा नांगलोई, किशनगंज, दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, जाकिर हुसैन कॉलेज आदि संस्थानों में शहीद भगत सिंह जयंती मनायी गयी।

दिल्ली के साथ लगते लोनी में भगत सिंह स्मृति सभा का दृश्य

प्रीतिलता वाद्देदार के शहीदी दिवस पर सभाएं

दिल्ली : केन्द्रीय मजदूर संगठन ऑल इण्डिया यूटीयूसी से सम्बद्ध दिल्ली आशा वर्कर्स एसोसिएशन (डीएडब्ल्यूए) द्वारा आजादी आन्दोलन की गैर समझौतावादी धारा की क्रान्तिकारी शहीद प्रीतिलता वाद्देदार के 82वें बलिदान दिवस पर उत्तरपूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार, पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर व दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी व उत्तर पश्चिम दिल्ली के नरेला में स्मृति सभाएं की गई। सभाओं को ऑल इण्डिया यूटीयूसी के दिल्ली राज्य सचिव व एसोसिएशन के अध्यक्ष कॉ. एम. चौरसिया, अंजू शर्मा, विजय लक्ष्मी, शिक्षा, रजनी, निर्मला, फरीदा, निर्वेश, रेखा बल्हारा ने सम्बोधित किया।

कॉ. हरीश त्यागी ने कहा कि शहीद प्रीतिलता ने अपने बलिदान से यह दिखा दिया कि जरूरत पड़ने पर महिलाएं भी देश की आजादी के लिए कुर्बानी दे सकती हैं। महिलाएं पुरुषों से किसी मायने में कम नहीं हैं। शोषणमुक्त समाज का उनका सपना आज भी अधूरा है। आशा कर्मियों को उनके साहस, कर्तव्यपरायणता और कुर्बानी की भावना व जीवन-संघर्ष से सीख लेकर अपने संगठन को मजबूत करते हुए अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। सभी आशा कर्मियों ने 6 नवम्बर को उपराज्यपाल कार्यालय पर प्रदर्शन की जोरदार तैयारी करने का संकल्प लिया।

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) की ओर से कॉ. सत्यवान द्वारा 3ए/38, डब्ल्यू.ई.ए., करोल बाग, नई दिल्ली-5 से संपादित व प्रकाशित तथा परम्परा प्रिंटिंग प्रेस, बी-70/83, इण्डस्ट्रियल एरिया, लॉरेंस रोड, दिल्ली-35 से मुद्रित, दूरभाष:011-25726631, Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com; sarvaharadrishtikon@yahoo.com